घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 199- गुरूवार 21 - मई 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

सुप्रीम कोर्ट ने जनगणना के दौरान जातिगत गणना को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

नई दिल्ली,20 मई 2026। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जाति के आधार पर जनगणना कराने के केंद्र के फैसले के खिलाफ याचिका खारिज कर दी और कहा कि यह मामला पॉलिसी के दायरे में आता है। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने की। बेंच याचिकाकर्ता सुधाकर गुम्मुला की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो अपने केस पर बहस करने के लिए खुद पेश हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को कल्याणकारी उपाय बनाने के लिए पिछड़ी जातियों के लोगों की संख्या पता होनी चाहिए। बेंच ने कहा, ये सब पॉलिसी से जुड़े मामले हैं, चाहे जनगणना जाति-आधारित हो या नहीं। इसमें गलत क्या है? सरकार को पता होना चाहिए कि पिछड़े वर्ग में कितने लोग हैं, उनके लिए किस तरह के कल्याणकारी कदम उठाए जाने हैं। बेंच ने याचिकाकर्ता को साफ कर दिया कि वह इस अर्जी पर सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। सीजेआई ने कहा, यह पॉलिसी के दायरे में है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि जाति का डेटा इकट्ठा करने का गलत इस्तेमाल हो सकता है, खासकर अगर यह जानकारी कॉर्पोरेट कंपनियों और नेताओं के हाथ लग जाए। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि जाति डेटा इकट्ठा करने का कोई औचित्य नहीं है। हालांकि, बेंच ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। 2027 की जनगणना, जो आधिकारिक 16वीं नेशनल जनगणना है, 1931 के बाद पहली बार होगी जिसमें पूरी जाति की गिनती शामिल होगी और यह देश की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी।

केजरीवाल,सिसोदिया और दुर्गेश पाठक को बड़ी राहत : चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट से खारिज

नई दिल्ली,20 मई 2026। आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल्ली हाईकोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है। अदालत ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक को चुनाव लड़ने से रोकने और आप का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की मांग वाली जनहित याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की और कहा कि यह पूरी याचिका बेहद गलत सोच और खराब मंशा पर आधारित है। अदालत में दायर इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि शराब नीति मामले की अदालती सुनवाई के दौरान इन नेताओं ने कोर्ट की कार्यवाही का एक तरह से बहिष्कार किया था। इसके अलावा यह भी दावा किया गया कि नेताओं ने सोशल मीडिया पर जजों के खिलाफ एक अभियान चलाया। याचिकाकर्ता का कहना था कि न्याय प्रणाली में जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए इन नेताओं को चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराया जाना चाहिए और उनकी पार्टी की मान्यता रद्द होनी चाहिए। फ शब्दों में कहा कि याचिका में जो भी मांगें की गई हैं, उनका कोई ठोस कानूनी आधार नहीं बनता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह जनहित याचिका सुनवाई के लायक ही नहीं है। लोकल रिपोर्टर के मुताबिक, याचिका में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दिया गया था। इसमें दावा किया गया था कि 27 अप्रैल 2026 को अरविंद केजरीवाल ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि वे आबकारी नीति मामले से जुड़ी कार्यवाही में जज के सामने न तो खुद पेश होंगे और न ही अपने वकील को भेजेंगे। बाद में मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक ने भी ऐसा ही किया।

अमेरिकी संसद में ईरान जंग रोकने वाला प्रस्ताव पास

ट्रम्प के 4 सांसदों ने उनके खिलाफ वोटिंग की,राष्ट्रपति के पास वीटो का अधिकार बाकी

वॉशिंगटन,20 मई 2026। अमेरिकी संसद में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की सैन्य शक्तियों को सीमित करने वाला प्रस्ताव पास हो गया है। वोटिंग में 4 रिपब्लिकन सांसदों ने भी विपक्षी पार्टी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। हालांकि 3 रिपब्लिकन सांसद वोटिंग में शामिल नहीं हुए। यह प्रस्ताव 50-47 से पास हुआ, हालांकि इसे कानून बनने के लिए अभी कुछ और चरणों से गुजरना होगा। अगर यह प्रस्ताव कानून बनता है, तो ट्रम्प सरकार को ईरान के खिलाफ युद्ध जारी रखने के लिए कांग्रेस की मंजूरी लेनी होगी। अभी सीनेट में इस पर अंतिम वोटिंग होनी बाकी है। इसके बाद इसे रिपब्लिकन बहुमत वाली हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से मंजूरी लेनी होगी। हालांकि उसके बाद भी ट्रम्प इसके खिलाफ वीटो कर सकते हैं। फिर उस वीटो को रद्द करने के लिए सीनेट और हाउस दोनों में दो-तिहाई बहुमत चाहिए होगा, जो फिलहाल मुश्किल माना जा रहा है। यह वोट विपक्ष के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है जो कह रहे थे कि अमेरिका में युद्ध शुरू करने या सेना भेजने का अधिकार राष्ट्रपति नहीं बल्कि संसद के पास होना चाहिए। अमेरिकी संविधान में भी यही व्यवस्था दी गई है। इस प्रस्ताव को वर्जीनिया के डेमोक्रेट सीनेटर टिम केन लेकर आए हैं।

राहुल गांधी की भाषा राजनीतिक हताशा दर्शाती है : अनुराग ठाकुर

शिमला,20 मई 2026। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई कथित अभद्र टिप्पणी की कड़ी निंदा की है। अनुराग ठाकुर ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि राहुल गांधी की भाषा, मानसिकता और व्यवहार उनकी राजनीतिक हताशा और बिगड़ी परवरिश को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में लगातार हार के बाद कांग्रेस नेतृत्व बौखलाहट में मर्यादा भूल चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि आत्ममंथन करने के बजाय कांग्रेस अपशब्दों की राजनीति पर उतर आई है। उन्होंने कहा कि जब भी देश पर कोई संकट आता है, तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े लोग जनता के साथ खड़े दिखाई देते हैं, जबकि राहुल गांधी जैसे नेता कठिन समय में विदेश चले जाते हैं। ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रति हल्की टिप्पणियां राहुल गांधी की राजनीतिक असुरक्षा और घबराहट को दर्शाती हैं। भाजपा सांसद ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और गांधी परिवार ने संविधान को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी संग की द्विपक्षीय वार्ता

भारत-इटली में हुई विशेष रणनीतिक साझेदारी

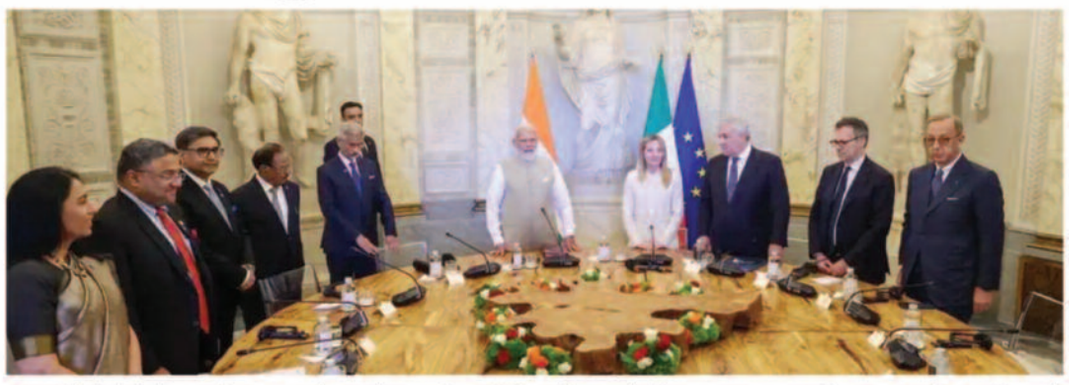

रोम,20 मई 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की अपनी समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इसके बाद संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत और इटली के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की। उन्होंने भारत- ईयू मुक्त व्यापार समझौते को पूरा करने में इटली के सहयोग के लिए मेलोनी को धन्यवाद भी दिया। उन्होंने कहा, हम मिलकर इसके जल्द से जल्द कार्यान्वयन की दिशा में काम करेंगे, ताकि कारोबारी समुदाय को इसका पूरा लाभ मिल सके।

प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करना मेरे लिए सम्मान की बात है। आज का दिन हमारे संबंधों के लिए सचमुच एक ऐतिहासिक दिन है। मेरे मित्र की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा है। इससे पहले किसी भारतीय प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय यात्रा 2000 में हुई थी। आज इस यात्रा के साथ, हम न केवल इस अंतराल को भर रहे हैं, बल्कि मिलकर हमने अपने संबंधों में नई जान डालने का भी फैसला किया है। प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ऊंचा उठाना पिछले 3 वर्षों में दोनों देशों के बीच हुई कई उच्च स्तरीय बैठकों के बाद हुआ है। इसमें 2023 में नई दिल्ली में एक रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत और पिछले साल ब्राजील में जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान 2025-2029 के लिए एक संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना पर हस्ताक्षर करना शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं रोम में राष्ट्रपति सर्जियो मट्टरेल्ला से मिला। हमने भारत और इटली के बीच जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की, जिसमें व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक संबंध शामिल हैं। हमने इस बात पर भी चर्चा की कि एआई, महत्वपूर्ण खनिज, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्र हमारे बीच सहयोग के अवसर कैसे बन सकते हैं। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि दोनों देशों के स्टार्टअप, अनुसंधान केंद्रों और उद्योगों को जोड़ने के लिए भारत-इटली नवाचार केंद्र बनाया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मोदी जी चाहते हैं कि जनता उनके भाषणों की मेलोडी का आनंद ले, जबकि उनकी सरकार की लूट से पैदा हुई तकलीफ को झेलती रहे!

पिछले 11 सालों में मोदी सरकार के राज में हर भारतीय पर औसत कर्ज 11 गुना बढ़ गया है। वहीं दूसरी ओर, 229 बड़े उद्योगपतियों और 26 नए अरबपतियों की कुल संपत्ति कथित तौर पर 97.50 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गई है।

पीएम मोदी ने मेलोनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट की...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट की। पीएम मेलोनी ने एक्स पर इस वीडियो को पोस्ट कर कहा- 'प्रधानमंत्री मोदी मेरे लिए गिफ्ट में बहुत-बहुत अच्छी टॉफी लेकर आए- मेलोडी। गिफ्ट के लिए थैंक्यू ' इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन (10 करोड़) से ज्यादा बार देखा गया। वहीं एक्स पर भी इसे 74 लाख से ज्यादा व्यू मिले।

राहुल गांधी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह को गद्दार कहा,बोले-मैं माफी नहीं मांगूंगा

रायबरेली/अमेठी,20 मई 2026। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रायबरेली में पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर अमर्यादित टिप्पणी की है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को गद्दार कहा। रायबरेली दौरे के दूसरे दिन राहुल ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले अमेठी में देश के पीएम पर जमकर बरसे। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को पर जमकर निशाना साधा।राहुल गांधी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को गद्दार कहते हुए कहा कि वो माफी नहीं मांगेंगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बुधवार को अमेठी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। मंच पर माइक हाथ में आते ही राहुल गांधी के तेवर काफी सख्त नजर आए। उन्होंने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि वे किसी से डरने वाले नहीं हैं। मैं माफी नहीं मांगूंगा, फिर बोलूंगा अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मैं इन लोगों से नहीं डरता हूं। हिंदुस्तान की जनता भी इस बात को समझ गई है, वो भी आपसे नहीं डरती है। आगे उन्होंने कहा कि पता नहीं आज आपने मोदी जी का वीडियो देखा कि नहीं देखा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों से सवाल करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी को टॉफी खिला रहे है। पीएम ने इटली जाने से पहले हिंदुस्तान से कहा कि खूब पेट्रोल का यूज़ कम करो। फिर उसी के एक दिन बाद 4000 करोड़ के हवाई जहाज में इटली गए। वहां के पीएम को टॉफी खिलाकर रील बनवा रहे हैं। देश की जनता के साथ यह क्या खिलवाड़ हो रहा है। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है। आने वाले दिनों में खाद नहीं मिलेगी। समय आने वाला है। ईरान में अमेरिका और ईरान की लड़ाई हुई, उसमें होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी के बाद पीएम मोदी ने रोते हुए कहा था मुझे फांसी पर चढ़ा देना, अगर काला धन खत्म नहीं हुआ। अब फिर से हाथ जोड़ने और रोने का टाइम आ रहा है। आप एक बात याद रखिए,नोटबंदी हिंदुस्तान के किसानों पर,मजदूरों पर, छोटे व्यापारियों पर आक्रमण था। नोटबंदी का लक्ष्य आपके जेब का पैसा, आपकी मेहनत का पैसा अडानी और अंबानी के हवाले करने का था। जब हमारे मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चल रहे थे। तब नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी का लाखों करोड़ों रुपए का कर्ज माफ कर रहे थे। अब देखिए, इन्होंने क्या किया। पब्लिक सेक्टर को खत्म कर दिया। फैक्ट्रियां बंद हो गई। किसान मजदूर कमजोर हो गए। पूरे देश में इन्होंने बेरोजगारी फैला दी। राहुल ने कहा कि हिंदुस्तान में आर्थिक तूफान आ रहा है। ऐसा तूफान आ रहा है, जो हिंदुस्तान में कभी नहीं आया था। नरेंद्र मोदी चुनाव के पहले कहते हैं कि तेल और गैस की कोई कमी नहीं है,सब कुछ ठीक है। हम दो महीने से कह रहे है। पार्लियामेंट में कहा, भाषणों में कहा कि 2 महीने से कहा,तब बीजेपी वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी को पिछले 3 महीने में जो सुधार करना था,नहीं किए। नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 साल से संविधान पर आक्रमण किया है। आरएसएस के लोगों को इलेक्शन कमीशन को पूरा कंट्रोल कर दिया। वोट चोरी का सिस्टम बना लिया। अडानी-अंबानी देश को नहीं बचा सकते है।

टेंशन में दुश्मन देश! भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में किया सूर्यास्त्र का सफल परीक्षण

बालासोर (ओडिशा),20 मई 2026। भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए पुणे की डिफेंस फर्म नीबे लिमिटेड ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। इस परीक्षण की सबसे खास बात यह रही कि, इस रॉकेट ने बहुत ही कम त्रुटि के साथ एकदम सटीक निशाना लगाया। ऐसे में इस सिस्टम को युद्ध तकनीक के लिहाज से बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। नीबे ग्रुप ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि 18 और 19 मई, 2026 को ओडिशा के चांदीपुर में अंतरिम टेस्ट रेंज में किए गए लगातार ट्रायल ने बहुत अच्छी सटीकता के साथ मिशन के सभी लक्ष्य पूरे किए। ये सफल परीक्षण 2026 में भारतीय सेना की ओर से कंपनी को दिए गए खरीद ऑर्डर के तहत किया गया है। इस अनुबंध ने सूर्यास्त्र यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर के विकास और सप्लाई को तेज कर दिया है।

साथ ही 150 किलोमीटर और 300 किलोमीटर रेंज वाले खास रॉकेट भी दिए। डिफेंस फर्म ने कहा कि सिस्टम ने दो दिन के परीक्षण के दौरान जबरदस्त सटीकता दिखाई। टेस्ट फायरिंग में कम, मध्यम और लंबी दूरी पर सिस्टम की प्रदर्शन को अच्छी तरह से जांचा गया। इस जांच में सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम ने जबर्दस्त प्रदर्शन करते हुए अचूक निशाना साधा।

हिंद महासागर पोत 'सुनयना' कोच्चि लौटा, वाटर कैनन सैल्यूट के साथ हुआ स्वागत

नई दिल्ली,20 मई 2026। भारतीय नौसेना का जहाज 'सुनयना' हिंद महासागर पोत (आईओएस) सागर 7 सप्ताह की यात्रा करने के बाद बुधवार को कोच्चि लौट आया। इस दौरान इस जहाज ने इंडो-पैसिफिक और हिंद महासागर क्षेत्र के सबसे स्ट्रेटेजिक रूप से अहम पानी में हजारों नॉटिकल मील की दूरी तय की। इस यात्रा में साझेदार रहे 16 देशों के 38 क्रू मेंबर्स के साथ यह संयुक्त मिशन पूरा करके भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में क्षेत्रीय समुद्री सहयोग और सामूहिक सुरक्षा को मजबूत किया। भारतीय नौसेना के साथ बांग्लादेश,इंडोनेशिया, केन्या, मलेशिया,मॉरीशस,मालदीव, मोजाम्बिक,म्यांमार,सेशेल्स, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, तिमोर लेस्ते और संयुक्त अरब अमीरात ने मिलकर यह तैनाती की थी। कोच्चि बंदरगाह लौटने पर आईएनएस सुनयना का वाटर कैनन सैल्यूट के साथ औपचारिक स्वागत किया गया। नौसेना की तेज इंटरसेप्टर नौकाओं से एस्कॉर्ट किए गए इस जहाज का दक्षिणी नौसेना कमान के अधिकारियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। जहाज के पहुंचने पर दक्षिणी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल समीर सक्सेना ने तैनाती के दौरान 16 देशों के 38 क्रू मेंबर्स के पेशेवर व्यवहार और बेहतरीन टीमवर्क को सराहा।

सरकार बदलते ही सीमा सुरक्षा पर बड़ा फैसला...शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ को 27 किलोमीटर लंबी जमीन सौंपने की शुरुआत की

कोलकाता,20 मई 2026। पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को 27 किलोमीटर लंबे क्षेत्र की जमीन सौंपने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को नवान्न में आयोजित पत्रकार वार्ता में इसकी घोषणा करते हुए अवैध घुसपैठियों के खिलाफ भी कड़ा रुख अपनाने का संकेत दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने बीएसएफ को जमीन हस्तांतरण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और अगले दो सप्ताह के भीतर प्रारंभिक चरण में 27 किलोमीटर क्षेत्र की जमीन उपलब्ध करा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भूमि एवं राजस्व सचिव तथा मुख्य सचिव को 45 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरी करने की जिम्मेदारी दी गई है। सुभेंदु अधिकारी ने कहा कि भारत-बांग्लादेश सीमा लगभग चार हजार किलोमीटर लंबी है, जिसमें से 2200 किलोमीटर हिस्सा पश्चिम बंगाल में पड़ता है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में अभी तक केवल 1600 किलोमीटर क्षेत्र में ही कंटीले तार लगाए जा सके हैं, जबकि लगभग 600 किलोमीटर क्षेत्र अब भी असुरक्षित है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने राजनीतिक कारणों और तुष्टीकरण की नीति के चलते बीएसएफ को आवश्यक जमीन उपलब्ध नहीं कराई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था, महिला सुरक्षा, जबरन धर्मांतरण और अन्य आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि देखी गई है तथा इनमें बड़ी संख्या अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अब सीमा सुरक्षा के मुद्दे पर बीएसएफ के साथ नियमित समन्वय बैठकें करेगी।

पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के दायरे में नहीं आने वाले लोगों को अवैध घुसपैठिया माना जाएगा। ऐसे लोगों को राज्य पुलिस गिरफ्तार कर बीएसएफ के हवाले करेगी, जिसके बाद उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में केंद्र सरकार ने गत वर्ष राज्य को दिशा-निर्देश भेजे थे, जिन्हें अब लागू किया जा रहा है।

राष्ट्रपति मुर्मु ने आईएएस अधिकारियों से कहा-भावुक हुए बिना संवेदनशील बनें

नई दिल्ली,20 मई 2026। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने बुधवार को कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों को करुणा और तर्कसंगतता के बीच संतुलन बनाना चाहिए तथा संवेदनशील होना चाहिए लेकिन भावुक नहीं। राष्ट्रपति भवन में विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में कार्यरत 2024 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारियों के एक समूह ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। इस दौरान राष्ट्रपति ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि अखिल भारतीय सेवाओं, विशेषकर आईएएस ने देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अब देश के विकास के नए चरण में प्रवेश करने के साथ अधिकारियों से अपेक्षाएं भी बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि युवा अधिकारियों को विविध क्षेत्रों में काम करने का अवसर मिलेगा और कई बार उन्हें विशेषज्ञों की टीमों का नेतृत्व भी करना पड़ेगा। ऐसे में उनके सीखने की गति और दायरा दोनों व्यापक होने चाहिए तथा विभिन्न परिस्थितियों और क्षेत्रों के अनुरूप स्वयं को ढालने की क्षमता असाधारण होनी चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि अधिकारियों की निष्पक्षता उनकी न्यायप्रियता का संकेत होगी,जबकि उनकी संवेदनशीलता समावेशिता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाएगी। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता और निरंतर प्रदर्शन से उनकी विश्वसनीयता बनेगी तथा व्यक्तिगत और पेशेवर आचरण से परिभाषित उनकी ईमानदारी उन्हें जनहित में निर्णायक कदम उठाने का नैतिक साहस देगी।

राष्ट्रपति ने कहा कि नैतिकता और सुशासन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अधिकारियों को ईमानदार और नैतिक होने के साथ-साथ परिणाम भी देने होंगे।

मेटा ने किया हजारों कर्मचारियों की छंटनी का ऐलान, एआई का असर

कंपनी ने चरणबद्ध तरीके से छंटनी की सूचनाएं भेजना किया शुरू

नई दिल्ली,20 मई 2026। मेटा प्लेटफॉर्म्स ने बुधवार को करीब 8,000 कर्मचारियों की छंटनी का ऐलान किया। इसकी वजह एआई के कारण संगठन का पुनर्गठन है। इसकी जानकारी कई रिपोर्ट्स में दी गई। फेसबुक की पेरेंट कंपनी ने चरणबद्ध तरीके से छंटनी की सूचनाएं भेजना शुरू कर दिया है, जिससे वैश्विक स्तर पर उसके करीब 10 फीसदी कर्मचारियों के प्रभावित होने और भूमिकाओं में बदलाव होने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि एक इंटरनल मेमो में मेटा की पुनर्गठन प्रक्रिया के तहत करीब 7,000 कर्मचारियों को एआई-केंद्रित नई भूमिकाओं में स्थानांतरित करने की योजना का जिक्र किया है। रिपोर्ट के मुताबिक कर्मचारियों को भेजे गए एक मेमो में मेटा की एचआर चीफ जेनेल गेल ने कहा कि कई टीमों को एआई-आधारित सिद्धांतों के आधार पर पुनर्गठित किया जा रहा है ताकि सरल संरचनाएं और छोटे समूह बनाए जा सकें जो ज्यादा जिम्मेदारी के साथ तेजी से काम किया जा सके। गेल ने कहा कि बदलावों पर काम करते हुए कई टीमों ने एआई-आधारित डिजाइन सिद्धांतों को अपनी नई संगठनात्मक संरचनाओं में शामिल किया।

संपादकीय

कोर्ट की सख्ती के मायने

इसमें दो राय नहीं कि स्थानीय निकायों द्वारा आवारा कुत्तों को हटाने के संबंध में विगत में दिए अपने निर्देशों को नरम न करने का सर्वोच्च न्यायालय का हालिया निर्णय, बिगड़ते जन-सुरक्षा संकट में एक आवश्यक हस्तक्षेप है। हाल के वर्षों में, देश भर में स्थानीय प्रशासन व निकाय कुत्तों के काटने की घटनाओं में लगातार हो रही चिंताजनक वृद्धि को रोकने में विफल ही रहे हैं। ऐसे में शासन व प्रशासन स्तर पर इस समस्या के निराकरण की कोई सार्थक पहल न होते देख ही, शीर्ष अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ा है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के अनुसार, साल 2023 में तीस लाख से अधिक कुत्तों के काटने के मामले दर्ज किए गए थे। उसके अगले साल 2024 में रोकथाम के कोई ठोस प्रयास न होने के कारण 37 लाख मामले दर्ज किए गए। आंकड़े बता रहे हैं कि औसतन प्रतिदिन दस हजार घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं कई राज्यों व शहरों में इन घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई है। हाल ही में सामने आए केरल के आंकड़ों के अनुसार, वहां एक साल के भीतर ही 3.6 लाख से अधिक कुत्तों के काटने के मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी दिल्ली से सटे नोएडा में कुछ ही महीनों में हजारों शिकायतों के बाद हॉटस्पॉट की पहचान की गई। इन शिकायतों में स्कूलों के पास उनका जमावड़ा होना,चलने में असमर्थ बुजुर्ग नागरिकों का शिकार बनना व आम नागरिकों के आवारा कुत्तों के भय में जीने के मामले उजागर हुए हैं। दरअसल,विगत में भी इस संकट के कारगर समाधान के लिये शीर्ष अदालत ने सख्त निर्देश दिए थे।

स्थानीय नगर निगम व नगर पालिकाओं की जवाबदेही तय की थी कि कुत्तों को शेल्टर होम ले जाकर उनकी नसबंदी की जाए और टीकाकरण किया जाए। लेकिन इस दिशा में कारगर पहल होती नजर नहीं आई। वहीं तसवीर का दूसरा पहलू है कि यह संकट समाज और संस्थाओं द्वारा जानवरों के प्रति किए जाने वाले व्यवहार में परेशान करने वाली विफलता को भी दर्शाता है। पिछले दिनों चंडीगढ़ से एक स्तब्धकारी घटना ने हर किसी संवेदनशील व्यक्ति को विचलित किया,जब एक अज्ञात व्यक्ति ने एक पिल्ले को धधकते तंदूर में फेंककर जिंदा जला दिया। ऐसे शर्मनाक कृत्य उस भयावह क्रूरता को उजागर करते हैं, जो सार्वजनिक चर्चाओं में उजागर नहीं होती। इस घटना ने इन जीवों की दयनीय स्थिति को ही उजागर किया। वहीं भूख से बिलबिलाते कुत्तों द्वारा कथित तौर पर अपने ही बच्चों को खाने के मामले भी शामिल हैं। शीर्ष अदालत की इस टिप्पणी से सहमत हुआ जा सकता है कि जानवरों के साथ मानवीय व्यवहार का मतलब नागरिकों की सुरक्षा की अनदेखी करना नहीं हो सकता। लेकिन इसके साथ ही जन सुरक्षा को पशु कल्याण की उपेक्षा का बहाना भी नहीं बनाया जा सकता है। निस्संदेह, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कानूनी रूप से जानवरों को स्थानांतरित करने पर दिए गए जोर के साथ अब आश्रय स्थलों, नसबंदी केंद्रों, टीकाकरण अभियानों और पशु चिकित्सा सुविधाओं में अधिक निवेश करने की सख्त जरूरत है। निश्चय ही यह चुनौती एक जटिल विषय है। सही मायनों में चुनौती यह भी है कि एक मानवीय, जवाबदेह और प्रभावी आवारा पशु प्रबंधन व्यवस्था का निर्माण किया जाए, जो नागरिकों और कुत्तों , दोनों के हितों की रक्षा कर सके। हमेशा से ही कुत्ते की गिनती मनुष्य के वफादार साथी के रूप में की जाती रही है। सदियों से दोनों एक साथ रहे हैं। उन कारणों की भी पड़ताल की जानी चाहिए, जिनके चलते कुत्ते अचानक आक्रामक व्यवहार दिखाने लगे हैं। निश्चय ही बढ़ता तापमान बदलते मौसमों के प्रति संवेदनशील इन जीवों को बेचैन किए हुए है।

पश्चिम बंगाल में ओबीसी कोटे पर नए फैसले से सुलगती सामाजिक और सियासी बिसात

कलकत्ता हाईकोर्ट ने जब इस पूरे मामले की परतें खोलीं,तो यह स्पष्ट हो गया कि बिना किसी व्यापक सर्वेक्षण या पिछड़ेपन के वैज्ञानिक मूल्यांकन के पूरी की पूरी आबादी को आरक्षण के दायरे में लाना संविधान के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है। अदालत के इसी फैसले को आधार बनाकर सुवेंदु सरकार ने 2012 के बाद की व्यवस्था को पूरी तरह रद कर 2010 की पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी है,जिसके तहत केवल 66 जातियां ही वैध रूप से ओबीसी कोटे की हकदार मानी गई हैं। इस सूची में कपाली,कुर्मी,नाई (नापित),तांती,धानुक,कसाई, खंडैत,तुरहा,पहाड़िया मुस्लिम,देवांगा और हज्जाम जैसी पारंपरिक जातियों को शामिल किया गया है...

संजय सक्सेना

पश्चिम बंगाल की राजनीति में आए हालिया बदलाव ने देश के सबसे संवेदनशील और पुराने विवाद को एक बार फिर हवा दे दी है आरक्षण, तुष्टिकरण और सामाजिक न्याय का असल चेहरा। राज्य में सत्ता परिवर्तन के तुरंत बाद मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की कैबिनेट ने जिस तरह से ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) सूची को लेकर कड़ा कदम उठाया है,वह महज एक प्रशासनिक आदेश नहीं बल्कि दशकों से चली आ रही 'वोटबैंक पॉलिटिक्स' की बुनियाद पर सीधा प्रहार है। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि उनकी सरकार ने मई 2024 में आए कलकत्ता हाईकोर्ट के उस ऐतिहासिक आदेश को जमीन पर उतारा है, जिसने राज्य में बिना किसी वैज्ञानिक सर्वे और ठोस डेटा के थोक के भाव बांटे गए ओबीसी प्रमाण पत्रों को असंवैधानिक करार दिया था। नई सरकार का पहला बड़ा राजनीतिक दांव यह रहा कि उसने सुप्रीम कोर्ट में पिछली ममता बनर्जी सरकार द्वारा दायर की गई पुनर्विचार याचिका को आधिकारिक तौर पर वापस ले लिया। इस एक फैसले ने साफ कर दिया कि नई व्यवस्था अब अदालत के रुख के साथ खड़ी है और 2012 के बाद से सामाजिक न्याय के नाम पर बुने गए उस जाल को पूरी तरह ध्वस्त करने जा रही है, जिसे विपक्षी दल 'मुस्लिम सब-कोटा' का शॉर्टकट बताते रहे हैं। इस पूरे विवाद की जड़ें साल 2010 से जुड़ी हैं, जब राज्य की तत्कालीन वामपंथी सरकार और उसके बाद सत्ता में आई तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने राज्य के भीतर एक ऐसा सामाजिक समीकरण तैयार करने की कोशिश की, जो चुनावी राजनीति में अजेय किला बन सके। ममता बनर्जी के कार्यकाल के दौरान पिछड़ा वर्ग सूची में 140 से ज्यादा नई उप-जातियों को जोड़ा गया था, जिनमें से करीब 80 फीसदी जातियां केवल एक विशेष समुदाय से थीं। आंकड़ों की बाजीगरी ऐसी थी कि 2011 की जनगणना के अनुसार बंगाल में रहने वाले करीब ढाई करोड़ मुसलमानों में से दो करोड़ से अधिक लोगों को कागजों पर रातों-रात 'ओबीसी' घोषित कर दिया गया। अत्यंत पिछड़ों के लिए बनी 'ओबीसी-ए' कैटेगरी में बड़े पैमाने पर मुस्लिम उप-जातियों को जगह मिलने का सीधा नतीजा यह हुआ कि नौकरियों और सरकारी शिक्षा संस्थानों में मिलने वाले कोटे पर एक खास वर्ग का वर्चस्व स्थापित होने लगा। इस पूरी प्रक्रिया ने उन मूल हिंदू पिछड़ी जातियों को हाशिए पर धकेल दिया, जो पीढ़ियों से अपने हक का इंतजार कर रही थीं। माहिष्य, सद्गोप, यादव और कुर्मी जैसी बड़ी पिछड़ी जातियां हों या फिर चुनिया और कलवार जैसे छोटे शिल्पी वर्ग, वे सभी संख्याबल और इस नए मुकाबले में पीछे छूटते चले गए। साथ ही, अनुसूचित जाति से ईसाई धर्म अपनाने वाले व्यक्तियों को भी इस सूची में स्थान मिला है। सरकार का अगला कदम और भी आक्रामक है, जिसके तहत 2011 के बाद से जारी किए गए सभी 1.69 करोड़ जाति प्रमाणपत्रों की व्यापक स्तर पर दोबारा जांच (री-वेरिफिकेशन) के आदेश दिए गए हैं। इसमें विशेष रूप से उन प्रमाण पत्रों को खंगाला जाएगा जो 'द्वारे सरकार' जैसे लोक-लुभावन कैंपों के जरिए आनन-फानन में बांटे गए थे। यह पूरा घटनाक्रम सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के कई अन्य सूबों में भी 'मजहब आधारित आरक्षण' बनाम 'संवैधानिक मर्यादा' की इस बहस को नए सिरे से जिंदा करता है। कर्नाटक में 1990 के दशक में मुस्लिमों के लिए ओबीसी सूची के तहत जो 4 फीसदी का सब-कोटा तय किया गया था, उसे मार्च 2023 में तत्कालीन सरकार ने असंवैधानिक बताते हुए खत्म कर दिया और मामला अब शीर्ष अदालत के विचाराधीन है। केरल में 1952 से ही लगभग पूरी मुस्लिम आबादी को पिछड़ा वर्ग का लाभ मिल रहा है, जहां हिंदू पिछड़ी जातियां लगातार आरोप लगाती रही हैं कि कोटे का बड़ा हिस्सा एक खास संपन्न वर्ग हड़प लेता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी पूरी आबादी को एकमुश्त आरक्षण देने के प्रयासों को अदालतों ने हमेशा खारिज किया है, जिसके बाद चुनिंदा जातियों को पहचान कर अलग कैटेगरी बनाई गई। इसके विपरीत बिहार जैसे राज्य में मंडल आयोग की सिफारिशों के तहत केवल पेशेवर और सामाजिक रूप से पिछड़ी मुस्लिम जातियों (जैसे अंसारी और कुरैशी) को ही अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) में रखा गया है। यह तुलना दिखाती है कि जब भी राज्य सरकारों ने वैज्ञानिक डेटा को दरकिनार कर केवल राजनीतिक लाभ के लिए एकमुश्त समुदायों को पिछड़ेपन का तमगा दिया, वहां कानूनी और सामाजिक टकराव होना तय था। संविधान का अनुच्छेद 16(2) स्पष्ट रूप से धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव या आरक्षण को प्रतिबंधित करता है, जबकि अनुच्छेद 15(4) केवल सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को ही आरक्षण का वैध आधार मानता है। 1992 के ऐतिहासिक इंद्रा साहनी मामले में देश की सर्वोच्च अदालत ने यह साफ कर दिया था कि गैर-हिंदू जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग में जोड़ा जा सकता है, लेकिन इसके

लिए उनका सामाजिक पिछड़ापन एक वैज्ञानिक पद्धति से सिद्ध होना अनिवार्य है। बंगाल में इसी संवैधानिक मर्यादा को ताक पर रखने का आरोप विपक्ष पर लगता रहा है, जहां मुस्लिम वोटबैंक को साधने के लिए जातियों के आंतरिक ढांचे की अनदेखी की गई। राजनीति की इस बिसात पर दोनों पक्षों के नियम एक-दूसरे से पूरी तरह उलट हैं। एक तरफ जहां बहुसंख्यक समाज को एकजुट रखने और 'सनातनी पहचान' के तहत क्षेत्रीय दलों के जातीय कार्ड को बेअसर करने की रणनीति चलती है, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समाज के भीतर की उस परत को खोलने का प्रयास हो रहा है जिसे मुख्यधारा की सेक्युलर राजनीति ने हमेशा छिपाकर रखा यानी 'अशराफ बनाम पसमांदा' का भेद। समाज के ऊंचे तबके (सैयद, शेख, पठान) ने हमेशा राजनीतिक और सामाजिक मलाई का आनंद लिया, जबकि जुलाहे, कसाई और बुनकर जैसे गरीब पिछड़े मुस्लिम समाज के हाशिए पर ही रहे। इसके विपरीत, क्षेत्रीय दलों का पूरा वजूद ही इस बात पर टिका है कि बहुसंख्यक समाज अपनी जातियों के छोटे-छोटे ब्लॉकों में बंटा रहे, ताकि 'जितनी आबादी, उतना हक' का नैरेटिव सेट किया जा सके। लेकिन जब बात अल्पसंख्यक समाज की आती है, तो यही दल कभी नहीं चाहते कि वह जातियों या अशराफ-पसमांदा के भेद में बंटें। वहां कोशिश यही होती है कि आंतरिक अंतर्विरोधों के बावजूद वे एक 'धार्मिक पहचान' के तहत एकमुश्त वोटबैंक बने रहें। इस्लामी धर्मशास्त्र के मुताबिक सैद्धांतिक तौर पर इस्लाम में ऊंच-नीच या जाति व्यवस्था का कोई स्थान नहीं है, और यही तर्क अक्सर आरक्षण के विरोध या समर्थन में धार्मिक मोड़ ले लेता है। लेकिन समाजशास्त्रियों का मानना है कि दक्षिण एशिया और खासकर भारत में, जिन जातियों का धर्मांतरण हुआ, वे अपनी धार्मिक पहचान बदलने के बाद भी अपनी सामाजिक-आर्थिक स्थिति और जातिगत पहचान को नहीं छोड़ पाईं। यही कारण है कि वैचारिक स्तर पर जातियों और फिरकों का विरोध करने वाले धार्मिक गुरु भी आरक्षण के सवाल पर चुप हो जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जमीनी स्तर पर मंसूरी या अंसारी की हालत किसी भी रूप में सैयद या शेख जैसी नहीं है। मजहब से बड़ी चुनौती व्यावहारिक पिछड़ापन है। बंगाल का यह नया फैसला देश की भांति-भांति की आरक्षण नीतियों के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, जो यह तय करेगा कि सामाजिक न्याय का तराजू केवल तुष्टिकरण के पलड़े से हिलेगा या फिर संविधान की कसौटी पर परखा जाएगा।

12वीं कक्षा के बाद का परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण में से एक है...

डॉ. विजय गर्ग

एक छात्र को जिन चौराहों का सामना करना पड़ता है। जबकि इंजीनियरिंग और चिकित्सा जैसे पारंपरिक मार्ग लोकप्रिय बने हुए हैं, आधुनिक परिदृश्य विशेष, कौशल-आधारित और अंतःविषय क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है। यहां उन प्राथमिक कैरियर धाराओं का अवलोकन दिया गया है जिन्हें छात्र आज अपना रहे हैं, तथा उन्हें उनके व्यावसायिक फोकस के आधार पर वर्गीकृत किया गया है।

1. पेशेवर एवं तकनीकी धाराएँ : ये लंबे समय से चल रहे 'फाउंडेशन' पाठ्यक्रम हैं, लेकिन नए विशेषज्ञता के साथ भी इनका विकास हो रहा है। इंजीनियरिंग (बी.ई./बी.टेक): मुख्य शाखाओं के अलावा, अब छात्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विज्ञान, साइबर सुरक्षा एवं रोबोटिक्स जैसे विषयों में भी भाग ले रहे हैं चिकित्सा एवं संबंधित विज्ञानः जो लोग एमबीबीएस की डिग्री नहीं ले रहे हैं, उनके लिए बी.एस.सी. की मांग बहुत अधिक है। नर्सिंग, फिजियोथेरेपी (बीपीटी), व्यावसायिक चिकित्सा एवं फार्मेसी

आर्किटेक्चर (बी. आर्क): भौतिक संरचनाओं की योजना, डिजाइन एवं निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है।

2. व्यवसाय,प्रबंधन और कानून

ये पथ उन छात्रों के लिए आदर्श हैं जिनके पास मजबूत नेतृत्व, विश्लेषणात्मक और संचार कौशल है। प्रबंधन (बीबीए/बीएमएस): यह कॉर्पोरेट जगत में प्रवेश करने का एक तरीका है; इसके बाद अक्सर एमबीए की डिग्री प्राप्त होती है। डिजिटल मार्केटिंग एवं बिजनेस एनालिटिक्स जैसी विशेषज्ञताएँ बहुत लोकप्रिय हैं। कानून (एक एकीकृत पांच वर्षीय कार्यक्रम): ऐसी संयुक्त डिग्रीएँ, जैसे कि बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी या बी.कॉम एलएलबी*, छात्रों को 12वीं कक्षा के बाद सीधे ही कानूनी अध्ययन शुरू करने में मदद करती हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंसी : ऑडिटिंग, कराधान एवं वित्तीय रिपोर्टिंग में रुचि रखने वालों के लिए यह एक कठिन प्रक्रिया है।

बोतलवासिनी शराब महारानी त्रिलोक गामिनी मायावी देवी की महिमा !

आत्माराम यादव पीव

हे त्रिलोक गामिनी बोतल वासिनि शराब महारानी ! समुद्रमंथन में सागर से आपका जन्म हुआ है तब से आप मदिरासुंदरी ने लाखों नही करोड़ों लोगों को अपना स्वाद चखाकर नालियों-गड्डों में ही त्रिलोक का भ्रमण किए बिना त्रिलोक का सुख देनेवाली हो ओर अपने बोतलरूपों के महाजाल में फाँसकर उन्हे जीवनमरण के कुचक्र से मुक्त कर असमय ही मृत्यु की आगोश में सुलानेवाली हो,इसलिए मैं आपके इस पुण्य प्रताप ओर महिमा को समझते हुये सभी के सामने आपका सही रूप रखते हुये आप बोतलनिवासिनी को शत शत प्रणाम करता हूँ ओर आपकी दीवानगी के शिकार हुये सारे बोतलानंदों को अग्रिम श्रद्धांजलि देते हुये उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूँ। हे रंगबिरंगी बोतलों की मलिका मैंने आपके कई रूप देखें है, आपके दीवाने हुये लोगों के अनेक ढंग देखें है, उन्हे जीता देखा है, उन्हे मरता देखा है। सदियों पहले मेरे यादव कुल के लोग तुझ अंगूर की बेटी को अपने होंठों से लगाने की गुस्ताखी कर चुके है, मेरे यादव कुल के ये लोग तुझे सोम सुंदरी कहकर तेरे पौराणिक महत्व सुधा सारिणी के जाल में आ गए और तुझे होंठो से लगा गटकते गए-गटकते गए और तब तक गटकते रहे जब तू उनके मस्तिष्क पर नृत्य करने लगी ...तेरा नाच सभी के मस्तिष्क में उत्पात मचाने लगा और सागर का वह तट जहा वे थे एक दूसरे के रक्तपिपासु हो एक दूसरे को मारने काटने लगे, ये तुम्हारा ही प्रताप था की जिस जिस ने तुझे होंठों से लगाया उन सभी के उदर में बस तू ही तू थी, तू सभी से मार काट कराकर सभी की मृत्यु का कारण बनी,इसलिए तेरा एक नाम सिर काटने वाली, सिर कटाने वाली भी है। देश और समाज में तुम्हारा निषेध है,अर्थात तुम बोतल निवासनी के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध है,पर इस प्रतिबंध के हर बन्ध पर कानून का ढक्कन खुला होने से तू बोतल वासिनी हर गली मोहल्ले में विधिवत घर घर पहुचाइ जाने से कानून के ढक्कनों सहित हे सर्वव्यापिनी तुम्हें प्रणाम है। हे मदिरे आपका यश वेदों ने गाया है, आप सभी के लिए सेव्य अमृत प्रवाह से जीवन में मदमस्त करने वाली साक्षात् महामाया भगवती का स्वरूप हो और सारा संसार आप में ही समाया हुआ है। क्या राजा? क्या प्रजा? क्या देश ? क्या देश के शासक सभी आप शराब देवी की शरण में है, इसलिए हे विलायत भूषण कच्ची महुआ सुता देवी, किसमें इतनी सामर्थ्य है जो आपको विस्मृत करने का दुस्साहस करे, इसलिए सभी आप मदिरा देवी की शरण पाकर अपने को धन्य समझते है, इसलिए हे शराब देवी हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए ओर हमे आशीर्वाद दीजिएगा की आपकी शरण में रहकर हम जगत से सारे वैभव ओर ऐश्वर्य का सुख भोगते हुये आप शराब की वैतरणी को पार कर सके। हे सकल मादक सामग्री शिरोरत्न आप सभी का प्रयोजन जगत के सभी मानवीय रक्त में प्रविष्ट होकर उन्हे खुद में एक महान व्यक्ति,एक स्वतंत्र आजाद धर्म का सारभूत समझना है,खुद को अवतार समझ कर जीना है इसलिए हे मयाबी शराब आपके प्रचार प्रसार हेतु कई नाम से आपकी महिमा गाई गई है और जगत के लोग आपको हे ब्रांडी,हे रम,हे जानिवाकर हे विस्की, हे वोदका,हे जिन,हे बीयर,हे वाइन,हे टकीला और शैंपेन नाम से परिचित है। जिसने भी आप मदिरा को आग्रह से प्रेम से अपने ओंठो पर छुआ वह निश्चित ही अपने कुल की मर्यादा को संहार कर अपने लिए शराबी,पियक्कड़,नशेवाज़ सहित अनेक नामों से घर समाज में पहचाना जाने लगता है। हे पंचमकार वर्णरूपी रूपसी! आप प्रपंचों कि देवी सुरा हो, शराब हो। आप शेंपिन का रूप धारण करती हो इसलिए तुम्हारे अनेक नाम है, अनेक रूप है ओर राजा से लेकर रंक तक तुम्हारे ही सेवक है इसलिए कोई भी तुम्हारा त्याग नही करना चाहता, इसलिए जोशीपुर नाला हो,लेडीया बाजार का गटर हो, बंगाली कालोनी, रसूलिया, कालिका नगर, वार्ड एक का नाला हो या मालाखेड़ी हो आप वहाँ रहने वाले पार्षदों , नेताओं आदि सहित पुलिस की भी आन, बान ओर शान हो। जिस मुहल्ले वार्ड या गली में आप गटर के ड्रमों में महुआ की महक के साथ अपना परिष्कृत रूप निखारकर ग्लासों में उतरकर ओंठ से पेट में प्रवेश करते हो ओर जिसके शरीर में कच्ची-पक्की शराब की तुकबंदी का निचोड़ पीने वाले को सिद्धात्मा बनाता हो ओर वह अपने कदमों पर नहीं दूसरे के कंधे के सहारे घर पहुंचता हो, तब आपके 100 टंच असली होने की प्रामाणिकता का सभी लोहा लेते हो, मैं उस सुरासुंदरी, बोतलनिवासनी, ड्रममालिका शराब को प्रणाम करता हूँ अतएव हे सिद्धे ! मेरा प्रणाम स्वीकारे, ओर आपके बाबत इस चर्चा को भी उदरस्थ करे, जो मैंने इस बोतल वासिनी की संगत न करके भोगी है। हे सामाजिक बुराइयों की अधिष्ठात्री देवी मदिरा सुंदरी, आपकी जय हो। मैं भी आपके पंचमहातंत्र के पुण्यप्रताप के मायाजाल में जकड़े बोतलनंदों के आनंद में खलल डालने की नीयत से खुद को शूरवीर समझ मैदान में उतरा ताकि लोग तेरे कच्ची शराब, पक्की शराब, व्हिस्की, रम आदि रूपों के मकडजाल से मुक्त हो सके। अवसर था मध्यप्रदेश सरकार के तत्कालीन दबंग उपमुख्यमंत्री सुभाषयादव जी आप सुरासुंदरी के चंगुल में असमय प्राण गवा रहे शराबियों को बचाने निकले थे तब मैं भी उनके आव्हान पर आपको प्रदेश निकाला दिये जाने हेतु अपने शहर को शराबमुक्त करने जुट गया, हालांकि न तो मैं आप बोतलनंदनी को जानता-पहचानता था ओर न ही आपसे कोई दुश्मनी थी ओर न आपने मेरा कुछ बिगाड़ा था, किन्तु समाज पर आप शराब का वर्चस्व था , जिसे मिटाना मैं समाज का धर्म समझकर मुहिम मे लग गया । सरकार ने नियम बनाया था जिस वार्ड की आधे से अधिक महिलाए हस्ताक्षर कर शराबसुंदरी का विरोध करे वहाँ आप शराब सुंदरी को बेदखल कर दिया जाएगा।

संजीव ठाकुर
रायपुर छत्तीसगढ़

विकास के साथ प्रकृति के विनाश की पटकथा लिख रहा मानव

वातावरण के प्रति संवेदनशील होना होगा...

आजादी हमें मिली है यानी कि मानव को परंतु प्रकृति आजादी से अछूती रही है। अमूमन हमारी जरूरत रोटी,कपड़ा,मकान और जल की थी फल स्वरुप हमको उद्योग धंधे का विकास तीव्र गति से करना पड़ा। मशीनें जीतनी बड़ी से बड़ी होती गई आदमी उतना ही बौना होता गया। कृषि में नई नई तकनीक ट्रैक्टर,रसायनिक उर्वरक,कीटनाशकों के प्रयोग से भूमि बंजर होकर कराहाने लगी। विकास का सही मायने माननीय शक्तियों के साथ ऊर्जा और उसकी शक्ति तथा सामर्थ्य का सही उपयोग ही होगा। जब से हमने विकास के पथ पर उड़ान भरी है उद्योगों की चिमनी यों को ऊपर उठाया मोबाइल क्रांति का बटन दबाया ई-मेल पर सवार होकर विश्व संदेश को सुना तब से हमारे झरनों का कल कल स्वर और संगीत बंद हो गया,पक्षियों का कलरव बंद हो गया पक्षी अब चीत्कार कर रहे हैं। नदी नाले सूखकर मृतप्राय हो गए हैं। समुद्र की लहरों की झंकार विलुप्त हो गई है और पानी खारा और खारा हो गया है। अब हमें यह सोचना है कि विकास के नाम पर हमें ग्रीन इंडिया चाहिए या इंटरनेट की सवारी कर डिजिटल इंडिया चाहिए। बच्चों की झोली में इंटरनेट को डालकर डिजिटल जेनरेशन का सपना देखना चाहिए या प्रकृति की गोद में सुगंधित वायु की लहरों में खो जाना चाहिए। झरनों में बैठकर नौका विहार का आनंद लेना चाहिए या कंप्यूटर में बैठकर नेट खोल कर नन्हे मुन्ने की आंखों पर जोर डालकर उन्हें चश्मा वाला बनाना चाहिए। हरा भरा हिंदुस्तान यानी कि ग्रीन इंडिया और डिजिटल इंडिया का सपना नदी के दो कभी ना मिलने वाले किनारे हैं। विकास के नाम पर असीमित उद्योग धंधों की बाढ़ आ गई है। भूमि समाप्त हो रही है साथ ही हमारी वायु विषैली हो गई है। रात में शहरी मकानों मैं बिजली के झालरों के सामने आकाश में रात्रि के तारों की चमक फीकी पड़ गई है। जंगलों को हम ऐसे साफ करते गए जैसे सड़क पर रोड रोलर चला रहे हैं। नगर बने,महानगर बने,मकान बने किंतु अब घर गायब होते गए, हमें तब सुध आई जब चिड़िया चुग गई खेत,हमें विकास के नाम पर मानव सभ्यता से जुड़ी जमीन पानी, हरियाली,पक्षी जानवर सब चाहिए केवल अंधाधुन्ध कंक्रीट का विकास या इंटरनेट की रफ्तार नहीं चाहिए। इसके लिए हमें संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग पर अंकुश लगाना होगा। संसाधनों का इस्तेमाल अतिरेक में नहीं होना चाहिए । महात्मा गांधी ने खुद कहा है कि पृथ्वी पर सभी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन है, किंतु मानव की लालच को पूरा करने का कोई साधन नहीं है। हम प्राकृतिक परियोजना तथा परिस्थितिकी की परियोजनाओं का स्वागत करना होगा सम्मान करना होगा। हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सौर, पवन,बायोगैस,ज्वार तरंग लहरों को ऊर्जा का आधार बनाना होगा।

आतंक के विरुद्ध भारत की निर्णायक लड़ाई और बदलती घाटी मिटानी होगी घाटी से आतंक की आखिरी परछाई

योगेश कुमार गोयल

भारत का इतिहास एक ओर जहां अध्यात्म,विविधता और समरसता की भूमि का रहा है, वहीं दूसरी ओर इसने अतीत और वर्तमान में अनेक आंतरिक और बाहरी संकटों का सामना भी किया है। इन संकटों में सबसे भयावह है आतंकवाद, जिसने न केवल देश की सुरक्षा व्यवस्था को लगातार चुनौती दी है बल्कि सामाजिक ताने-बाने को भी झकझोरा है। आतंकवाद कोई सीमित भूभाग का संकट नहीं है बल्कि यह समूचे राष्ट्र की चेतना को आहत करने वाला संकट है। भारत ने सैन्य,कूटनीतिक,सामाजिक और वैचारिक मोर्चों सहित बहुस्तरीय स्तर पर दशकों तक इस समस्या का सामना किया है। आतंकवाद के विरूद्ध जागरूकता फैलाने और शांति एवं सद्भाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 21 मई को 'राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस' मनाया जाता है। 21 मई को मनाया जाने वाला यह दिवस न केवल इस संघर्ष की स्मृति है बल्कि यह ऐसी प्रतिज्ञा का दिन भी है, जो यह दर्शाती है कि भारत आतंकवाद को किसी भी रूप में सहन नहीं करेगा। कश्मीर घाटी आतंकवाद के विरुद्ध भारत के सबसे लंबे, संवेदनशील और निर्णायक संघर्ष की साक्षी रही है। कभी अपनी अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता,सूफी परंपराओं, सांस्कृतिक समृद्धि और 'धरती के स्वर्ग' की पहचान के लिए विख्यात यह घाटी पिछले तीन दशकों तक आतंक, रक्तपात और अस्थिरता के भयावह दौर से गुजरती रही। वर्ष 1990 के बाद जिस सुनियोजित तरीके से घाटी में कट्टरपंथ और आतंकवाद की जड़ें जमाई गई, वह केवल स्थानीय असंतोष नहीं बल्कि सीमापार रची गई एक गहरी साजिश का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य भारत की एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता को चोट पहुंचाना था। इस दौर ने हजारों परिवारों को उजाड़ दिया, अनगिनत मासूमों की जिंदगी छीन ली और पूरी पीढ़ी को भय, असुरक्षा और हिंसा के साए में जीने के लिए विवश कर दिया। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि घाटी में अब तक हुई हजारों आतंकी घटनाओं में लगभग 42 हजार लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें निर्दोष नागरिक,सुरक्षाबलों के वीर जवान और आतंकवादी शामिल हैं। दक्षिण एशिया आतंकवाद पोर्टल की रिपोर्ट के अनुसार,वर्ष 2000 से 2024 के बीच घाटी में 22,143 छोटे-बड़े आतंकी हमले दर्ज किए गए, जिनमें 4,981 आम नागरिकों की मौत हुई जबकि मातृभूमि की रक्षा करते हुए 3,624 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए। इसी दौरान भारतीय सेना और सुरक्षा बलों ने अदम्य साहस और रणनीतिक क्षमता का परिचय देते हुए 24,512 आतंकवादियों को मार गिराया। यह केवल आंकड़े नहीं बल्कि उन वीर जवानों के अद्वितीय शौर्य, बलिदान और राष्ट्रनिष्ठा की गाथा हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित की। हालांकि बीते एक दशक में भारत की आतंकवाद विरोधी नीति अधिक आक्रामक,तकनीक-सक्षम और रणनीतिक रूप से प्रभावी हुई है। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2004 से 2014 के बीच देशभर में 7,217 आतंकी हमले हुए थे जबकि वर्ष 2014 से 2024 के बीच यह संख्या घटकर 2,242 से भी कम रह गई। इस दौरान आतंकी हिंसा से होने वाली जनहानि में 70 प्रतिशत से अधिक कमी दर्ज की गई। आम नागरिकों की मौतों में 81 प्रतिशत और सुरक्षाकर्मियों की शहादतों में लगभग 50 प्रतिशत की गिरावट इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भारत की मजबूत सुरक्षा रणनीति, सशक्त खुफिया तंत्र और 'जीरो टॉलरेंस' नीति ने आतंकवाद की कमर तोड़ने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। हालांकि आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि आतंकवाद की चुनौती कितनी गहन और विस्तृत है तथा इससे निपटने के लिए भारत को कितनी रणनीतिक गहराई के साथ काम करना पड़ रहा है। 2025 के पहलगाम हमले से इतर देखें तो घाटी में हाल के वर्षों में सामान्य जीवन की बहाली का प्रमाण यही है कि आज वहां के युवा बंदूक नहीं, किताबों की ओर लौट रहे हैं। स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ी है,कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में दाखिलों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और पर्यटन के क्षेत्र में भी आशाजनक वृद्धि देखी गई है। रोजगार के अवसरों में बढ़ोत्तरी ने युवाओं को एक वैकल्पिक जीवन की राह दिखाई है। इन संकेतों से स्पष्ट है कि आतंक केवल सैन्य शक्ति से नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास से भी पराजित किया जा सकता है। घाटी की जनता अब समझ चुकी है कि आतंक का मार्ग केवल विनाश की ओर ले जाता है जबकि शिक्षा, रोजगार और शांति समृद्धि की ओर। लेकिन इस यात्रा में अब भी चुनौतियां शेष हैं क्योंकि पाकिस्तान अब भी दोहरी नीति अपनाए हुए है।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटाराअम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।
-सम्पादक

ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ सरगुजा के केमिस्ट एकजुट

मेडिकल दुकानें बंद,शहर में निकाली बाइक रैली,सरकार को दी आंदोलन तेज करने की चेतावनी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,20 मई 2026
(घटती-घटना)।

ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री के विरोध में बुधवार को सरगुजा संभाग के दवा कारोबारियों ने एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद की। ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन (एआईओसीडी) के आह्वान पर अंबिकापुर सहित पूरे संभाग की मेडिकल दुकानें बंद रहीं। दवा व्यापारियों ने इसे केवल व्यवसाय का नहीं, बल्कि जन-स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया। सरगुजा औषधि विक्रेता संघ के नेतृत्व में शहर के अग्रसेन चौक से बाइक व स्कूटी रैली निकाली गई। रैली जयस्तंभ चौक,महामाया चौक,संगम चौक,देवीगंज रोड होते हुए घड़ी चौक पहुंची। इस दौरान केमिस्टों ने ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार से इस व्यवस्था पर सख्त नियंत्रण लगाने की मांग की। दवा व्यापारियों का कहना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए बिना पर्याप्त निगरानी के दवाइयों की बिक्री हो रही है, जो आने वाले समय में बड़ा स्वास्थ्य संकट खड़ा कर सकती है। उनका आरोप है कि ऑनलाइन खरीदी जा रही दवाओं की गुणवत्ता, भंडारण और वास्तविक स्रोत की विश्वसनीय जांच नहीं हो पा रही है। इससे नकली, एक्सपायरी अथवा गलत दवाइयों के उपयोग का खतरा बढ़ रहा है। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि दवा कोई सामान्य वस्तु नहीं है जिसे बिना चिकित्सकीय सलाह और उचित निगरानी के खरीदा-बेचा जाए। उन्होंने चिंता जताई कि ऑनलाइन माध्यमों से प्रतिबंधित और नशीली दवाओं की पहुंच भी आसान हो रही है, जिससे युवाओं में दुरुपयोग की आशंका बढ़ रही है।

सेहत से समझौता स्वीकार नहीं

रैली के दौरान दवा कारोबारियों ने कहा कि लोग कपड़े, मोबाइल या अन्य सामान ऑनलाइन खरीद सकते हैं,लेकिन दवा सीधे लोगों की जिंदगी और स्वास्थ्य से जुड़ी होती है। ऐसे में इसकी बिक्री पर सख्त नियम और जवाबदेही जरूरी है। संघ के अनुसार वर्तमान व्यवस्था में ऑनलाइन कंपनियां भारी छूट देकर ग्राहकों को आकर्षित कर रही हैं, जबकि स्थानीय मेडिकल संचालकों को कड़े नियमों का पालन करना पड़ता है। इससे पारंपरिक मेडिकल व्यवसाय भी प्रभावित हो रहा है।

सरकार को दी आंदोलन तेज करने की चेतावनी

सरगुजा औषधि विक्रेता संघ ने स्पष्ट कहा कि यदि सरकार ने ऑनलाइन दवाओं की अनियंत्रित बिक्री पर ठोस कदम नहीं उठाया तो आने वाले दिनों में आंदोलन और उग्र किया जाएगा। संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी है। व्यापारियों का कहना है कि उनका उद्देश्य केवल अपने व्यवसाय को बचाना नहीं,बल्कि लोगों को सुरक्षित और प्रमाणित दवाइयां उपलब्ध कराना है। उन्होंने सरकार से ऑनलाइन दवा कंपनियों के लिए कड़े नियम लागू करने और निगरानी तंत्र मजबूत करने की मांग की।

मरीजों को राहत देने वैकल्पिक व्यवस्था

मेडिकल दुकानें बंद रहने का असर शहर और आसपास के मरीजों पर भी दिखाई दिया। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर जरूरी दवाओं की उपलब्धता बनाए रखने के लिए कुछ वैकल्पिक केंद्र खुले रखे गए थे। आपातकालीन स्थिति को देखते हुए शासकीय अस्पतालों के दवा केंद्र, जनऔषधि केंद्र,धन्वंतरी मेडिकल स्टोर तथा अन्य जरूरी औषधि केंद्रों से मरीजों को दवाइयां उपलब्ध कराई गईं,ताकि उपचार प्रभावित न हो।

अंबिकापुर में हत्या का सनसनीखेज मामला...24 घंटे के भीतर आरोपी गिरफ्तार

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,20 मई 2026
(घटती-घटना)।

शहर के मणिपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर में हुई महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया। नगर पुलिस अधीक्षक राहुल बंसल के मार्गदर्शन में मणिपुर थाना एवं साइबर सेल की संयुक्त टीम ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जहां उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी कैलाश राम पिता अघनू राम निवासी ग्राम कुरहटेपना, बगीचा जिला जशपुर ने 19 मई 2026 को थाना मणिपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी चचेरी बहन सुखमनिया अपने पति जमुना चिकवा के साथ ट्रांसपोर्ट नगर में रहती थी। पड़ोसियों से उसकी मृत्यु की सूचना मिलने पर वह अंबिकापुर पहुंचा, जहां उसने देखा कि मृतका के पैर, कमर और पीठ पर डंडे से मारपीट के गंभीर निशान थे। इस आधार पर उसने अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या किए जाने की आशंका जताई। रिपोर्ट पर थाना मणिपुर में अपराध क्रमांक 101/2026 धारा 103(1) बी.एन.एस. के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। शव पंचनामा की कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया

तथा आरोपी की तलाश शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस टीम ने आरोपी के संभावित ठिकानों पर दबिश दी और अंततः आरोपी जमुना चिकवा पिता स्वर्गीय रामबिलास चिकवा उम्र 35 वर्ष निवासी कुमनसिया चौकी केरजू थाना सीतापुर,हाल मुकाम कदमपारा ट्रांसपोर्ट नगर मणिपुर जिला सरगुजा को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने हत्या करना स्वीकार कर लिया। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने 20 मई 2026 को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। पूरे मामले की कार्रवाई में थाना प्रभारी मणिपुर उप निरीक्षक सी.पी. तिवारी,सहायक उप निरीक्षक अजीत कुमार मिश्रा,अनिल पाण्डेय सहित थाना एवं साइबर सेल के कई अधिकारियों और जवानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि, जीईसी अंबिकापुर को मिली एमबीए समेत नए कोर्सों की स्वीकृति

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,20 मई 2026
(घटती-घटना)।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अंबिकापुर को बड़ी सौगात दी है। परिषद ने महाविद्यालय में एमबीए सहित कार्यरत पेशेवरों के लिए विशेष बीटेक और एमटेक पाठ्यक्रमों को मंजूरी प्रदान की है। इस निर्णय से सरगुजा संभाग के विद्यार्थियों और तकनीकी कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है। अब तक विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, अंबिकापुर के नाम से संचालित संस्थान को आधिकारिक तौर पर शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय (जीईसी),अंबिकापुर नाम दिया गया है। कॉलेज प्रबंधन ने इसे संस्थान की स्वतंत्र पहचान और तकनीकी शिक्षा के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। एआईसीटीई से मिली स्वीकृति के तहत महाविद्यालय में एमबीए पाठ्यक्रम की 30 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। वहीं

नौकरीपेशा तकनीकी कर्मचारियों के लिए विशेष बीटेक एवं एमटेक कोर्स भी शुरू किए जाएंगे। विशेष बीटेक पाठ्यक्रम में सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और माइनिंग इंजीनियरिंग में 30-30 सीटें स्वीकृत हुई हैं। वहीं एमटेक में माइनिंग इंजीनियरिंग, पावर सिस्टम एंड कंट्रोल तथा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में 15-15 सीटों की मंजूरी मिली है। कॉलेज प्रबंधन के अनुसार शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अंबिकापुर प्रदेश का पहला शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय बन गया है, जहां एमबीए के साथ-साथ कार्यरत पेशेवरों के लिए एक साथ तीन-तीन विषयों में विशेष बीटेक और एमटेक पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जा रहे हैं। इन कोर्सों की कक्षाएं जुलाई 2026 से शुरू होंगी। नई व्यवस्था से सरगुजा और आसपास के आदिवासी व दूरस्थ क्षेत्रों के युवाओं को बड़ा लाभ मिलेगा। अब उच्च तकनीकी शिक्षा के लिए बड़े शहरों की ओर पलायन कम होगा। नौकरी करते हुए तकनीकी शिक्षा हासिल करने का अवसर मिलने से युवाओं की रोजगार क्षमता और कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा।

कॉलेज प्रबंधन ने बताया कि यह उपलब्धि सांसद चिंतामणि महाराज के प्रयासों तथा अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल, युवा आयोग के अध्यक्ष विश्वविजय सिंह तोमर और पार्षद आलोक दुबे के सहयोग से संभव हो सकी है। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. (डॉ.) राम नारायण खरे ने एआईसीटीई, राज्य शासन, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी जनप्रतिनिधियों, छात्र संगठनों और महाविद्यालय परिवार के प्रति आभार जताया है।

विश्व मधुमक्खी दिवस पर किसानों को किया गया जागरुक

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,20 मई 2026
(घटती-घटना)।

राजमोहिनी देवी कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र तथा परिक्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र,अम्बिकापुर के संयुक्त तत्वावधान में विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजमोहिनी देवी कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र, अम्बिकापुर के अधिष्ठाता डॉ. एसके सिंहा एवं विशिष्ट अतिथि परिक्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, अम्बिकापुर के सह संचालक अनुसंधान डॉ. केएल पैकरा, अखिल भारतीय समन्वित मधुमक्खी पालन एवं परागण सहायक कीट अनुसंधान परियोजना के मुख्य अन्वेषक डॉ. पीके भगत द्वारा विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों, विद्यार्थियों एवं आमजन को मधुमक्खी पालन के महत्व तथा कृषि उत्पादन में परागण की भूमिका के प्रति जागरूक करना। इस अवसर पर विशेषज्ञों ने मधुमक्खियों के संरक्षण, शहद उत्पादन की उन्नत तकनीकों एवं स्वरोजगार की संभावनाओं पर विस्तार से जानकारी दी। अधिष्ठाता डॉ. एसके सिंहा ने बताया कि मधुमक्खियां कृषि उत्पादन बढ़ाने,जैव विविधता संरक्षण एवं पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मधुमक्खी पालन न केवल अतिरिक्त आय का सशक्त माध्यम है, बल्कि ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर भी प्रदान करता है। कार्यक्रम में आदरणीय सह संचालक अनुसंधान डॉ. केएल पैकरा ने मधुमक्खी कालोनी प्रबंधन, शहद उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन संबंधी तकनीकी जानकारी प्रदान की गई। डॉ. पीके भगत द्वारा ने बताया कि विश्व मधुमक्खी दिवस मधुमक्खी के संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता हैं मधुमक्खी से हमें शहद, मोम, रॉयल जेली, पराग, प्रोपोलिस तथा मधुमक्खी का विष उत्पादन कर अतिरिक्त लाभ प्राप्त किया जाता हैं। डॉ आरएस सिदार ने मधुमक्खी के लिये सालभर फूल वाले खेती की जानकारी दिया गया। डॉ. सचिन कुमार जायसवाल द्वारा वैज्ञानिक विधि से शहद निकालकर जीवंत प्रदर्शन दिखाया गया साथ ही लोगों को बताया गया कि शुद्ध शहद खाने से शरीर में रोगप्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों द्वारा विश्व मधुमक्खी दिवस का पंपलेट का विमोचन किया गया साथ ही सभी उपस्थित विद्यार्थियों को मधुमक्खी संरक्षण एवं संवर्धन का संकल्प दिलाया गया तथा मधुमक्खी पालन को अपनाकर आत्मनिर्भर बनने हेतु प्रेरित किया गया।

निगम के 11 होर्डिंग्स जोन पर टेंडर हुआ मार्च को 07 जोन का...अब तक नहीं हुआ अनुबंध... फिर होर्डिंग्स का पैसा किसकी जेब में...?

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,20 मई 2026 (घटती-घटना)।

नगर निगम अम्बिकापुर में होर्डिंग्स और विज्ञापन बोर्ड को लेकर एक बार फिर विवाद गहराता नजर आ रहा है। समाजसेवी एवं भाजपा नेता कैलाश मिश्रा ने निगम प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि शहर के 11 होर्डिंग्स जोन से जुड़े 07 जोन का टेंडर मार्च माह में हो चुका है,लेकिन अब तक संबंधित एजेंसी के साथ विधिवत अनुबंध नहीं किया गया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि इन होर्डिंग्स और फ्लैक्सी से मिलने वाला पैसा आखिर किसकी जेब में जा रहा है? कैलास मिश्रा ने आरोप लगाया कि नगर निगम में पारदर्शिता की जगह भाई-भतीजावाद और मनमानी को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शहर में बड़े पैमाने पर विज्ञापन फ्लैक्सी और होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं,लेकिन निगम के राजस्व खाते में उसका स्पष्ट हिसाब दिखाई नहीं दे रहा। इससे राजस्व चोरी की आशंका और मजबूत हो रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब मार्च में टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी तो अब तक अनुबंध क्यों नहीं किया गया? यदि अनुबंध नहीं हुआ तो फिर विज्ञापन बोर्ड लगाने और उनसे वसूली करने की अनुमति किसके आदेश पर दी जा रही है? आखिर इन फ्लैक्सी और होर्डिंग्स से मिलने वाली राशि किसके पास पहुंच रही है? भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि निगम के कुछ जिम्मेदार अधिकारी और प्रभावशाली लोग मिलकर पूरे मामले में गोलमाल कर रहे हैं। निगम की संपत्तियों और विज्ञापन स्थलों का उपयोग नियमों के विरुद्ध किए जाने से नगर निगम को लाखों रुपये के राजस्व नुकसान की बात भी कही गई है। कैलाश मिश्रा ने मांग की है कि होर्डिंग्स और फ्लैक्सी से जुड़े पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। साथ ही यह सार्वजनिक किया जाए कि वर्तमान में शहर में लगे विज्ञापन बोर्डों से निगम को कितना राजस्व प्राप्त हुआ और कितना बकाया है। इस मामले को लेकर शहर की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है। निगम प्रशासन की ओर से अब तक कोई स्पष्ट जवाब सामने नहीं आने से चर्चाओं का बाजार गर्म है। अब देखना होगा कि निगम प्रशासन इन आरोपों पर क्या सफाई देता है और मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है।

अंबिकापुर में भीषण गर्मी पारा 42 डिग्री,लोग बेहाल

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,20 मई 2026 (घटती-घटना)।

पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता कमजोर पड़ते ही सरगुजा संभाग में एक बार फिर भीषण गर्मी का असर तेज हो गया है। पिछले दो दिनों से तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बुधवार को अंबिकापुर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तेज धूप और लू की थपेड़ों से जनजीवन प्रभावित हो गया है। सुबह 10 बजे के बाद ही सडक़ों पर लोगों की आवाजाही कम हो जा रही है, जबकि दोपहर में शहर के प्रमुख चौक-चौराहों पर सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। पिछले एक सप्ताह से पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में बदलाव बना हुआ था। दोपहर बाद आंधी और हल्की बारिश होने से तापमान में गिरावट आई थी और अधिकतम तापमान 36 से 37 डिग्री के आसपास पहुंच गया था। लेकिन सोमवार से मौसम साफ होते ही गर्मी ने फिर तेवर दिखाने शुरू कर दिए। सोमवार को तापमान सीधे 40 डिग्री तक पहुंच गया था, जबकि मंगलवार को इसमें एक डिग्री से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

अभी गर्मी से राहत के आसार नहीं...

मौसम वैज्ञानिक एसके मंडल के अनुसार उत्तरी छत्तीसगढ़ में फिलहाल गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है। आने वाले दिनों में तापमान में और वृद्धि हो सकती है। सरगुजा संभाग इस समय लू की चपेट में है और देर शाम तक गर्म हवाएं चल रही हैं। शाम 6 बजे के बाद भी लू का असर महसूस किया जा रहा है।

राब के नशे में पत्नी की पिटाई,अंदरूनी चोट से मौत पीएम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि,आरोपी पति गिरफ्तार

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,20 मई 2026
(घटती-घटना)।

शहर के ट्रांसपोर्टनगर क्षेत्र में किराए के मकान में रहने वाली महिला की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने उसके पति को गिरफ्तार किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मारपीट से लगी अंदरूनी चोट के कारण मौत की पुष्टि हुई है। पुलिस पूछताछ में आरोपी पति ने शराब के नशे में पत्नी की पिटाई करना स्वीकार किया है। जानकारी के अनुसार सीतापुर क्षेत्र निवासी 32 वर्षीय सुखमनिया चिकवा अपने पति जमुना चिकवा और दो मासूम बच्चों के साथ ट्रांसपोर्टनगर के कदमपारा स्थित एक किराए के मकान में रहती थी। उसका पति हमाली का काम करता है। सोमवार रात पति-पत्नी ने साथ में शराब पी थी। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। गुस्से में पति ने डंडे से पत्नी की पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि मारपीट के बाद दोनों सो गए। मंगलवार सुबह पति काम के लिए बलरामपुर जिले के कुसमी चला गया। सुबह करीब 9 बजे तक जब महिला कमरे से बाहर नहीं निकली तो मकान मालकिन और पड़ोसी वहां पहुंचे। कमरे के अंदर महिला की औंधे मुंह अर्धनग्न हालत में लाश पड़ी थी। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई।

पीएम रिपोर्ट से खुला हत्या का राज : सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। शुरुआती जांच में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर के अंदर गंभीर चोट मिलने से मौत की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने पति जमुना चिकवा को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में उसने शराब के नशे में पत्नी के साथ मारपीट करना स्वीकार कर लिया। पुलिस के अनुसार महिला के शरीर पर बाहरी चोट के निशान ज्यादा नहीं थे। मारपीट के बाद दोनों सो गए थे। सुबह करीब 4 बजे पति काम पर निकल गया था। उसे पत्नी की मौत की जानकारी बाद में पुलिस से मिली।

डायल 112 (फेज-2) सेवा का शुभारंभ, अंबिकापुर में 12 हाईटेक ERV वाहन तैनात

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,20 मई 2026
(घटती-घटना)।

अंबिकापुर में डायल 112 (फेज-2) सेवा का शुभारंभ किया गया। राजेश अग्रवाल ने रक्षित केंद्र ग्राउंड में 12 हाईटेक इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। छत्तीसगढ़ शासन की इस नई व्यवस्था के तहत पुलिस, एम्बुलेंस, अग्निशमन, महिला हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन, आपदा प्रबंधन एवं नेशनल हाईवे सहायता जैसी सभी आपातकालीन सेवाओं को एकीकृत कर नंबर 112 से जोड़ा गया है। नई ERV गाड़ियों में GPS, डैश कैमरा, PTZ कैमरा और मोबाइल डेटा टर्मिनल जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे आपात स्थिति में त्वरित सहायता मिल सके। कार्यक्रम में प्रबोध मिंज,मंजूषा भगत,दीपक झा,राजेश अग्रवाल सहित जिले के अधिकारी एवं थाना प्रभारी उपस्थित रहे।

भाजपा सरगुजा जिला प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ

राजेश अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं को राष्ट्रहित एवं संगठनात्मक दायित्वों का दिया संदेश

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,20 मई 2026
(घटती-घटना)।

राजेश अग्रवाल ने कहा कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं और संगठन की विचारधारा पहुंचाने का कार्य कर रहा है।

अम्बिकापुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान 2026 अंतर्गत भाजपा सरगुजा जिला का दो दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग संगठनात्मक गरिमा एवं उत्साह के साथ प्रारंभ हुआ। उद्घाटन सत्र में प्रशिक्षणार्थी कार्यकर्ताओं का पंजीयन किया गया तथा प्रदर्शनी दर्शन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा भाजपा का ध्वजारोहण एवं दीप प्रज्ज्वलन किया गया। प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र में प्रशिक्षण वर्ग जिला प्रभारी ज्योतिनंद दुबे, भाजपा सरगुजा संभाग प्रभारी अवधेश

चंदेल, जिला सह प्रभारी कृष्णकांत चन्द्रा एवं सुनील गुप्ता की विशेष उपस्थिति रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया ने की। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल ने 'देश के समक्ष चुनौतियाँ' विषय पर अपने विचार रखते हुए कहा कि आज भारत वैश्विक स्तर पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन सामाजिक,वैचारिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी अनेक चुनौतियाँ भी देश के सामने मौजूद हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन की रीति-नीति को जन-जन तक पहुंचाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।

स्वागत उद्बोधन एवं वक्ता परिचय देते हुए जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया ने प्रशिक्षण वर्ग की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं को संगठन की विचारधारा,कार्यपद्धति एवं दायित्वों से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में सांसद चिंतामणि महाराज,विधायक प्रबोध मिंज,विधायक रामकुमार टोप्पो,महापौर मंजूषा भगत, हरपाल सिंह भामरा,जिला पंचायत अध्यक्ष निरूपा सिंह, ललन प्रताप सिंह,अम्बिकेश केशरी,विनोद हर्ष,अरुणा सिंह सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे।

आये दिन बिजली कटौती से आमजन हलाकान,कोई सुनने वाला नहीं-बेलगाम हो गया है बिजली विभाग : दीपक गर्ग

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,20 मई 2026
(घटती-घटना)।

भीषण गर्मी के बीच शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार हो रही बिजली कटौती को लेकर आमजन में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। घंटों तक बिजली गुल रहने से लोगों का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। इसी बीच भाजपा नेता दीपक गर्ग ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि लगातार हो रही अघोषित कटौती से जनता त्रस्त हो चुकी है,लेकिन जिम्मेदार अधिकारी समस्या के समाधान के प्रति गंभीर नजर नहीं आ रहे। दीपक गर्ग ने कहा कि दिन हो या रात, बिना सूचना बिजली बंद कर दी जाती है। छोटे व्यापारी,छात्र,मरीज और आम परिवार सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। गर्मी के इस मौसम में लोगों को पीने के पानी तक की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इन्वर्टर जवाब दे चुके हैं और लोग रातभर जागने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग पूरी तरह बेलगाम हो चुका है। शिकायत करने पर उपभोक्ताओं को संतोषजनक जवाब नहीं मिलता। कई बार फोन तक रिसीव नहीं किए जाते। आम जनता खुद को ठगा और उपेक्षित महसूस कर रही है। सोशल मीडिया और विभिन्न मंचों पर भी लोग लगातार बिजली व्यवस्था को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। देश के कई राज्यों में भी बिजली कटौती और अव्यवस्था को लेकर विरोध प्रदर्शन सामने आए हैं। भाजपा नेता दीपक गर्ग ने कहा कि चूंकि प्रदेश में भाजपा की सरकार है,इसलिए पार्टी और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। उन्होंने सुझाव दिया कि भाजपा को एक विशेष कमेटी गठित करनी चाहिए,जो क्षेत्र में हो रही बिजली कटौती, ट्रांसफार्मर खराबी,लो-वोल्टेज और मेंटेनेंस व्यवस्था की जमीनी जांच करे। यह कमेटी आम जनता से संवाद कर वास्तविक समस्याओं को समझे और समाधान के लिए विभागीय अधिकारियों पर दबाव बनाए। उन्होंने कहा कि जनता को यह भी बताया जाना चाहिए कि आखिर कटौती किन कारणों से हो रही है और समाधान के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। पारदर्शिता की कमी के कारण लोगों में असंतोष लगातार बढ़ रहा है। यदि जल्द सुधार नहीं हुआ तो जनता का गुस्सा बड़ा आंदोलन का रूप ले सकता है।

कटकोना-रजपुरीकला सड़क निर्माण की मांग, ग्रामीणों ने एसडीएम को दिया 10 दिन का अल्टीमेटम

-संवाददाता-
लखनपुर,20 मई 2026
(घटती-घटना)।

कटकोना से पुहपुटरा,सिरकोतंगा होते हुए रजपुरीकला (एसईसीएल) पहुंचने वाले जर्जर मार्ग को लेकर ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों में गुस्सा फूट पड़ा है। कांग्रेस प्रदेश सचिव रणविजय सिंहदेव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज लखनपुर तहसील कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और सड़क के शीघ्र निर्माण की मांग की। प्रदेश सचिव रणविजय सिंहदेव ने ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि कटकोना से पुहपुटरा, सिरकोतंगा होते हुए रजपुरीकला तक जाने वाला यह मार्ग एसईसीएल विश्रामपुर क्षेत्र के

अधीन आता है। कई वर्षों से यह मार्ग बेहद दयनीय स्थिति में है। बार-बार शिकायत और मांग के बावजूद अब तक इसकी मरम्मत या नई सड़क नहीं बन पाई है। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, मजदूर और वाहन इस मार्ग से रोजाना आवागमन करते हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन को 10 दिनों का समय देते हुए चेतावनी दी कि यदि इस अवधि में सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन, खदान बंदी और चक्का जाम किया जाएगा।

एसडीएम का आश्वासन : लखनपुर के एसडीएम ने ज्ञापन प्राप्त करते हुए कहा कि मामले की जानकारी उच्चाधिकारियों को भेज दी जाएगी। उच्च स्तर से निर्देश मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जा सकेगी। ज्ञापन सौंपने के दौरान कांग्रेस प्रदेश सचिव रणविजय सिंहदेव के साथ जिला उपाध्यक्ष कृपाशंकर गुप्ता,जनपद सदस्य धर्मेंद्र कुमार झारिया,मुकेश सिंह,सुजीत गुप्ता,मोहरलाल राजवाड़े,प्रदीप राजवाड़े,गौकरण सिंह,सियांबर राजवाड़े,पुहपुटरा सरपंच गोविंद सिंह सहित कटकोना,पुहपुटरा और सिरकोतंगा के सरपंच एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। स्थानीय लोग लंबे समय से इस मार्ग की बेहतर स्थिति की मांग कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन और एसईसीएल इस मांग पर कितनी तेजी से अमल करता है, या फिर यह मुद्दा फाइलों में दबकर रह जाएगा।

तहसील परिसर बना जंग का मैदान,जमीन विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट

-संवाददाता-
वाड्रफनगर,20 मई 2026
(घटती-घटना)।

जमीन विवाद से जुड़ी सुनवाई के दौरान मंगलवार को तहसील परिसर अचानक रणभूमि में तब्दील हो गया। सुनवाई के लिए पहुंचे दो पक्षों के बीच पहले तहसील न्यायालय के भीतर तीखी बहस हुई, जो देखते ही देखते गाली-गलौच और मारपीट में बदल गई। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि दोनों पक्षों को न्यायालय कक्ष से बाहर निकालना पड़ा, लेकिन बाहर निकलने के बाद भी विवाद शांत नहीं हुआ और तहसील व सिविल कोर्ट परिसर में दोनों पक्ष फिर आमने-सामने आ गए। जानकारी के अनुसार, तहसीलदार न्यायालय में आवेदक इलियासुदीन पिता जलालूदीन एवं अनावेदक पक्ष रसीद पिता इलियास, अफजल पिता इलियास तथा इलियास पिता इस्ताज के बीच जमीन से जुड़े प्रकरण की सुनवाई चल रही थी। इसी दौरान अनावेदक पक्ष के कुछ लोग और उनके साथ पहुंचे गवाह कथित रूप से दूसरे पक्ष के अधिवक्ता सिद्दिकी के साथ अभद्रता करने लगे। देखते ही देखते मामला गरमा गया और दोनों पक्षों के बीच धक्का-मुक्की एवं मारपीट शुरू हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, तहसील परिसर में कुछ समय तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। विवाद बढ़ता देख मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव करने का प्रयास किया, वहीं सूचना मिलते ही पुलिस भी सक्रिय हुई। घटना के कारण न्यायालयीन कार्यवाही कुछ समय के लिए प्रभावित रही। मामले को गंभीरता से लेते हुए गुरुदत्त पंचभावे ने न्यायालय की गरिमा भंग करने, शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने तथा शांति व्यवस्था प्रभावित करने के आरोप में दोनों पक्षों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।

नाम परिवर्तन सूचना

मै सुनीता नारंग (पुराना नाम, यदि बदला गया है) सुपुत्र/सुपुत्री श्री चंद्रकांत अच्चगले गाँव/शहर गुतुरमा, पो0 गुतुरमा, तहसील सीतापुर जिला -सरगुजा छ0ग0 राज्य ने अपना नाम सुनीता अच्चगले (पुराना नाम) से बदल कर सुनीता नारंग (नया नाम) रख लिया है।

आवेदक
सुनीता नारंग
सीतापुर जिला -सरगुजा छ0ग0

नाम परिवर्तन सूचना

मैं ढ़ोलू आ0 स्व0 अमीर साय, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी- ग्राम विशुनपुर (खुर्द), पो0- राघवपुरी, तहसील-अम्बिकापुर, जिला- सरगुजा छत्तीसगढ़ का है। यह कि मैं उपरोक्त पते का स्थायी निवासी हूँ। मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम ढ़ोलू (DHOLU) के स्थान पर त्रुटिवश महावीर अंकित हो गया है। मेरे आधार कार्ड में मेरा वास्तविक नाम ढ़ोलू (DHOLU) करने हेतु स्वयं का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

शपथग्रहिता
ढ़ोलू आ0 स्व0 अमीर साय,
निवासी- ग्राम विशुनपुर (खुर्द),
पो0- राघवपुरी, तहसील-
अम्बिकापुर, जिला- सरगुजा
छत्तीसगढ़

हरी झंडी दिखाकर इमरजेंसी डायल 112 सेवा का शुभारंभ,24 घंटे मिलेगी त्वरित पुलिस सहायता

-संवाददाता-
बलरामपुर/राजपुर,20 मई 2026
(घटती-घटना)।

जिले में आमजन की सुरक्षा एवं त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इमरजेंसी डायल 112 सेवा का विधिवत शुभारंभ किया गया। पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में प्रतापपुर विधायक शकुंतला पोर्ते ने 10 इमरजेंसी डायल 112 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जानकारी के अनुसार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा 18 मई 2026 को पूरे राज्य में 400 डायल 112 वाहनों को रवाना किया गया था। इसी क्रम में जिला बलरामपुर में भी डायल 112 सेवा को प्रभावी रूप से शुरू किया गया। कार्यक्रम का आयोजन पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर के कुशल मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विश्व दीपक त्रिपाठी के निर्देशन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में सांसद सरगुजा चिंतामणी महाराज ने ऑनलाइन वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर आमजन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि डायल 112 सेवा से लोगों को आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित सहायता मिल सकेगी और पुलिस व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। जिला पुलिस द्वारा बताया गया कि डायल 112 सेवा के माध्यम से सड़क दुर्घटना, मारपीट, चोरी, महिला सुरक्षा, घरेलू विवाद, फायर ब्रिगेड एवं एम्बुलेंस जैसी आपात स्थितियों में तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। आम नागरिक किसी भी संकट की

स्थिति में डायल 112 पर कॉल कर तत्काल पुलिस सहायता प्राप्त कर सकते हैं। पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर ने बताया कि डायल 112 सेवा 24 घंटे संचालित रहेगी तथा जिले के सभी क्षेत्रों में सक्रिय रूप से कार्य करेगी। प्राप्त सूचनाओं पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई कर पीड़ितों तक समय पर सहायता पहुंचाई जाएगी। कार्यक्रम में जिला वन मंडल अधिकारी आलोक बाजपेयी, जिला पंचायत सीईओ नयनतारा सिंह सहित जनप्रतिनिधि, पुलिस विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। जिला पुलिस बलरामपुर ने आमजन से अपील की है कि किसी भी आपात स्थिति में बिना घबराए डायल 112 पर संपर्क करें तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। साथ ही फर्जी एवं अनावश्यक कॉल करने से बचें, ताकि वास्तविक जरूरतमंदों को समय पर सहायता मिल सके।

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,
रा.प्र.क्र./अ-20(1)/2025-26
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती निलिमा तिवारी आ0 मनोज कुमार तिवारी जाति, निवासी केदारपुर, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा मोहल्ला - केदारपुर, शीट नम्बर-4 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 1951 / 59 रकबा 0.05 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 03-06-2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। निय तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा।

आज दिनांक 18/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

नजूल अधिकारी
,अंबिकापुर

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर जिला-सरगुजा,छत्तीसगढ़
ईश्तहार

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक कृष्णा प्रसाद आ0 मनबहाल निवासी रामपुर थाना अम्बिकापुर तहसील ने कराया है कि आवेदक के अपने दादी (स्व0 धनेश्वरी पति स्व0 गनपद की दिनांक 12/03/2003 को स्थान निवास में हुई है।

आवेदक के मृत्यू उपरांत मृत्यू का पंजीयक नहीं कराया गया है । अतः प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होने पर यह आवेदन पेश किया गया है।
उक्त संबंध में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो ईश्तहार प्रकाशन से 15 दिवस तक न्यायलय में उपस्थित होकर अपना दावा / आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। समय-सीमा के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

आज दिनांक 07/04/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालीन मुद्रा से जारी ।

तहसीलदार
अंबिकापुर,सरगुजा

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,
रा.प्र.क्र./अ-20(1)/2025-26
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक किरण वर्मा आ0 / पति स्व0 राजेन्द्र प्रसाद वर्मा जाति, निवासी महामाया रोड़ अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा मोहल्ला बौरीपारा, शीट नम्बर-4 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 2038/6 रकबा 0.30 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 03/06/2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा।

आज दिनांकः- 13/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

नजूल अधिकारी
,अंबिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,
रा.प्र.क्र./अ-20(1)/2025-26
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मनोज कुमार तिवारी आ0 स्व0 एच0के0 तिवारी जाति निवासी केदारपुर, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा मोहल्ला - केदारपुर, शीट नम्बर-1 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 192/5, 193/13 रकबा 980.10, 1197.10 वर्गफीट भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो, अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 03-06-2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। तिथि के बाद प्राप्त दावा /आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा।

आज दिनांक 18/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

नजूल अधिकारी
,अंबिकापुर

कार्यालय नगर पंचायत–लखनपुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)

Ph. 07774-261501 email-cmolakhanpur@gmail.com

कमांक / 637 / लो.नि./ न.पं. / 2026-27 लखनपुर,दिनांक- 18/05/2026

द्वितीय ई-प्रोक्योरमेंट निविदा सूचना

नगर पंचायत लखनपुर में एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत निविदाकारों से निर्माण कार्यों हेतु ऑनलाईन निविदा आर्मंत्रित की जाती है -

System Tender no	Estimated Amount (Lakh)	Earnest Money Deposit	Bid Submission Start Date & Time	Bid Due Date & Time	Physical Document Submission Date &Time	Bid Open Date & Time
191194	19.18	14500/-	18/05/2026 17.30 PM after	02/06/2026 Before 17.30 PM	05/06/2026 Before 14.00 PM	05/06/2026 After 15.00 PM
191195	78.79	59100/-	18/05/2026 17.30 PM after	02/06/2026 Before 17.30 PM	05/06/2026 Before 14.00 PM	05/06/2026 After 15.00 PM
191196	46.74	35000/-	18/05/2026 17.30 PM after	02/06/2026 Before 17.30 PM	05/06/2026 Before 14.00 PM	05/06/2026 After 15.00 PM

टीप-
01. उपरोक्त कार्यों की निविदा की समान्य शर्तें धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति निविदा दस्तावेत व अन्य जानकारी ई-प्रोक्योरमेंट वेब पोर्टल https:egeprocurement.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है।
02. विज्ञापन की प्रति https:cg.uad.gov.inमें देखी जा सकती है।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पंचायत लखनपुर
जिला - सरगुजा (छ0ग0)

शायर-ए-शहर' यादव विकास का निधन साहित्य जगत में शोक की लहर

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,20 मई 2026
(घटती-घटना)।

यादव विकास का 86 वर्ष की आयु में 19 मई को निधन हो गया। उनके निधन से साहित्य, सामाजिक और सांस्कृतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। नगर में वे 'शायर-ए-शहर' के नाम से विशेष रूप से पहचाने जाते थे और अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों के दिलों में अलग पहचान बना चुके थे। बताया गया है कि वे पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे। उपचार के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर मिलते ही साहित्य प्रेमियों, शुभचिंतकों और परिचितों में शोक व्याप्त हो गया। उनका अंतिम संस्कार 20 मई को शंकरघाट में किया गया। मुखाग्नि उनके ज्येष्ठ पुत्र श्रीकुमार यादव ने दी। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता,मित्रगण एवं नगरवासी उपस्थित रहे और नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। स्वर्गीय यादव विकास अपने पीछे दो पुत्र एवं चार पुत्रियों सहित भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं। उनके निधन को नगर के साहित्यिक जगत के लिए अपूरणीय क्षति माना जा रहा है।

तीन साल से फरार धोखाधड़ी का आरोपी बिहार से गिरफ्तार,भेजा गया जेल

-संवाददाता-
वाड्रफनगर,20 मई 2026
(घटती-घटना)।

धोखाधड़ी के एक पुराने मामले में लंबे समय से फरार चल रहे शातिर आरोपी को पुलिस ने सीतामढ़ी से गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। मामले में वाड्रफनगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थाना वाड्रफनगर में अपराध क्रमांक 10/2024 के तहत

धारा 420 एवं 34 भा.दं.वि. के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था। प्रार्थी ओम प्रकाश कुशवाहा ने वर्ष 2024 में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया था कि 'हमारी दिशा हमारे कदम' नामक संस्था, दिल्ली के संचालक राजेश कुमार एवं उसके सहयोगी मनोज चौहान द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान कई गांवों में सैनिटाइजर छिड़काव का कार्य कराया गया था। आरोप है कि संस्था संचालकों ने कार्य दिलाने और भुगतान करने के नाम पर छलपूर्वक करीब 9 लाख 30 हजार रुपये की राशि ले ली, लेकिन बाद में भुगतान नहीं किया।

कार्यालय कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग (भ/स) अम्बिकापुर मण्डल अम्बिकापुर

निविदा आमंत्रण तिथि - 15/05/2026

ई-प्रोक्योरमेंट निविदा सूचना

1. निविदा की विस्तृत जानकारी के लिये Lig in करें http://eproc,csstate.gov.in
2. संबंधित संभाग- अम्बिकापुर संभाग
3. स.क्रं. - 01 से 06 'द' वर्ग एवं ऊपर ठेकेदार
4. ऑनलाईन निविदा डालने की अंतिम तिथि - 08.06.2026

स. क्र.	एन.आई. टी.क्र.	कार्य की अनुमानित लागत लागत (रू0 लाख)	अमानत लागत (लाख में)
1	2	3	4
1	19	लोक निर्माण विभाग (भ / स) उपसंभाग क्र. 2 अम्बिकापुर के अंतर्गत विभिन्न शासकीय आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों का रंगाई पोताई का कार्य (प्रथम आमंत्रण)	15.07
2	20	लोक निर्माण विभाग (भ / स) उपसंभाग क्रं. 2 अम्बिकापुर के अंतर्गत विभिन्न शासकीय आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों का साधारण मरम्मत का कार्य (प्रथम आमंत्रण)	15.00
3	21	लोक निर्माण विभाग (भ / स) उपसंभाग सीतापुर के अंतर्गत विभिन्न शासकीय आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों का विशेष मरम्मत का कार्य (प्रथम आमंत्रण)	30.00
4	22	लोक निर्माण विभाग (भ/स) उपसंभाग क्र. 2 अम्बिकापुर के अंतर्गत विभिन्न शासकीय आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों का विशेष मरम्मत का कार्य (प्रथम आमंत्रण)	60.00
5	23	लोक निर्माण विभाग (भ / स) उपसंभाग क्र. 1 अम्बिकापुर के अंतर्गत विभिन्न शासकीय आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों का विशेष मरम्मत का कार्य (प्रथम आमंत्रण)	70.00
6	24	जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में जिला परिवहन कार्यालय भवन, चेकपोस्ट (घुटरी टोला का निर्माण कार्य (प्रथम आमंत्रण)	40.67

कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग
अम्बिकापुर मण्डल,अम्बिकापुर

जी0नं0 -262700801/4

सायरन, स्टिकर और सत्ता का शो-रूम!

कोरिया से अंबिकापुर तक VIP संस्कृति का खुला खेल, हूटर से लेकर पदनाम तक सड़कों पर दौड़ 'रौब राज'

जनप्रतिनिधि हों या प्रशासनिक अधिकारी नियमों को सलाम, रुतबे को प्रणाम!

व्हीआईपी बनने की ऐसी होड़ कि कानून भी किनारे खड़ा देख रहा तमाशा

मोटर व्हीकल एक्ट साफ कहता है कि हूटर और सायरन का उपयोग केवल पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और कुछ विशेष सुरक्षा वाहनों को ही अनुमति है, लेकिन जिले में कई निजी वाहन ऐसे घूम रहे हैं जिनमें हूटर ऐसे फिट हैं जैसे वाहन कंपनी की ओर से ही लगाए गए हों, लोगों का कहना है कि यदि कोई आम युवक अपनी बाइक में प्रेशर हॉर्न लगा ले तो पुलिस उसका चालान काट देती है,लेकिन जब रसूखदारों की महंगी गाड़ियों में सायरन बजता है तो नियम शायद खुद किनारे खड़े होकर सलामी देने लगते हैं,स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस इन वाहनों को रोज सड़कों पर देखते हैं,लेकिन कार्रवाई न होना अपने आप में बड़ा सवाल है।

अब गाड़ियों में पदनाम का प्रदर्शन भी बना नया फैशन

यदि बात केवल हूटर तक सीमित होती तो शायद मामला इतना चर्चित नहीं होता,अब तो निजी वाहनों में बड़े-बड़े बोर्ड लगाकर पद की प्रदर्शनी भी शुरू हो गई है, कहीं जनपद सदस्य,कहीं अध्यक्ष,कहीं तहसीलदार, कहीं एसडीएम,तो कहीं सीईओ जिला पंचायत जैसे कई पद नाम वाले बोर्ड गाड़ियों में चमकते दिखाई देते हैं,कई वाहनों की नंबर प्लेट के ऊपर इतना बड़ा पदनाम लिखा होता है कि असली नंबर खोजने के लिए अलग से मेहनत करनी पड़ जाए,ऐसा प्रतीत होता है जैसे वाहन नहीं,चलता-फिरता सरकारी परिचय पत्र सड़क पर दौड़ रहा हो।

निजी वाहन या चलता-फिरता कार्यालय?

कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की निजी गाड़ियों को देखकर आम लोग भी भ्रमित हो जाते हैं कि यह सरकारी वाहन है या निजी,बड़े-बड़े अक्षरों में पदनाम लिखे होने के कारण ऐसा लगता है मानो पूरा विभाग ही गाड़ी पर चिपका दिया गया हो,लोगों का कहना है कि जिन अधिकारियों को सादगी और अनुशासन का उदाहरण होना चाहिए,वही लोग अपने पद का प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं,कई लोगों ने व्यंग्य करते हुए कहा कि अब शायद अगला दौर ऐसा आएगा जब गाड़ियों में फाइल अंदर है, कलेक्टर से सीधे संपर्क और रौब ऑन ड्यूटी जैसे स्लोगन भी लिखे दिखाई देंगे।

जनता पूछ रही – क्या नियम सिर्फ आम लोगों के लिए हैं?

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या नियम केवल आम जनता के लिए बनाए गए हैं? यदि कोई आम नागरिक वाहन की नंबर प्लेट में थोड़ा बदलाव कर दे तो तुरंत चालान हो जाता है,यदि कोई बाइक चालक थोड़ा तेज हॉर्न बजा दे तो पुलिस पकड़ लेती है,लेकिन जब वही काम रसूखदार लोग करते हैं तो पूरा सिस्टम मौन क्यों हो जाता है? लोगों का कहना है कि कानून की असली परीक्षा वहीं होती है जहां कार्रवाई प्रभावशाली लोगों पर करनी पड़े,आम आदमी पर नियम लागू करना आसान है,लेकिन सत्ता और प्रभाव वाले लोगों पर कार्रवाई करना ही प्रशासन की वास्तविक निष्पक्षता साबित करता है।

-रवि सिंह-

कोरिया/एमसीबी,20 मई 2026 (घटती-घटना)। देश में वर्षों पहले लालबत्ती संस्कृति खत्म करने की घोषणा बड़े जोर-शोर से हुई थी,कहा गया था कि लोकतंत्र में कोई व्हीआईपी नहीं होगा, जनता सबसे बड़ी होगी और जनप्रतिनिधि खुद को जनता का सेवक समझेंगे। लेकिन जमीनी हकीकत अब कुछ और ही कहानी बयान कर रही है, लालबत्ती भले हट गई हो, मगर व्हीआईपी बनने की बीमारी आज भी सरकारी गलियारों और नेताओं की गाड़ियों में पूरी रफ्तार से दौड़ रही है।

कोरिया,एमसीबी,सूरजपुर, बलरामपुर और अंबिकापुर जिलों में इन दिनों सड़कों पर एक नई संस्कृति दिखाई दे रही है सायरन संस्कृति, स्टिकर संस्कृति और पद प्रदर्शन संस्कृति, कहीं जनप्रतिनिधियों की निजी गाड़ियों में अवैध हूटर बज रहे हैं, तो कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की निजी गाड़ियों में बड़े-बड़े पदनाम वाले बोर्ड लटक रहे हैं, ऐसा लगने लगा है जैसे सड़कें अब यातायात के लिए कम और रुतबे की प्रदर्शनी के लिए ज्यादा इस्तेमाल हो रही हैं।

संपूर्ण भारत के लिए एक प्रकाशन | घटती घटना | कोरिया-सूरजपुर-समाचार | अम्बिकापुर,बुधवार 02 जुलाई 2025 | 5

क्या वर्तमान सहित पूर्व जनप्रतिनिधियों में रुतबे के लिए है हूटर प्रेम...

रुतबे के लिए हूटर मामले में कानून की नेता उड़ा रहे धज्जियां?

आम आदमी को कानून का पाठ सिखाने वाली पुलिस दंड देने वाली पुलिस नेताओं के मामले मौन क्यों?

क्या कोरिया जिले की पुलिस हूटरबाज नेताओं पर करेगी कार्यवाही,क्या नेताओं की गाड़ियों से उतरेगा हूटर,लगेगा जुर्माना?

त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की गाड़ियों में हूटर लगाया जाना और बेवजह बजाया जाना आम,पुलिस कार्यवाही का भी नहीं खौफ?

पुलिस भी नेताओं के मामले में मौन,आम गरीब इंसान की छोटी सी भी यातायात गलती पर हजारों जुर्माना लगाने केवल तत्पर

क्या कोरिया जिले के पूर्व नेताओं की गाड़ियों पर पुलिस करेगी चालानी कार्यवाही जिनमें लगा है अवैध रूप से हूटर?

हूटर लगाने का अधिकार केवल इमरजेंसी सेवाओं में एम्बुलेंस,फायरब्रिगेड,पुलिस को,अन्य को हूटर बेचने वाले दुकानों पर फिर क्यों नहीं होती कार्यवाही?

क्या नेता खुद उतारेंगे अपनी गाड़ियों से हूटर या पुलिस करेगी चालानी कार्यवाही या फिर हूटरों वाले वाहनों की संख्या और बढ़ेगी?

जिला पंचायत अध्यक्ष,जनपद अध्यक्ष,उपाध्यक्ष, जनपद सदस्य सभी की गाड़ियों में लगे हैं हूटर,पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवाल

पुलिस भी नेताओं के मामले में मौन,आम लोगों के लिए पुलिस नियम मामले में प्रतिबद्ध

हूटर बेचने वालों पर आखिर क्यों नहीं होती कार्यवाही?

हूटर बजा... जनता समझी कोई बड़ा अफसर आ रहा है!

जिले के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों हूटर बजाती गाड़ियां किसी फिल्मी दृश्य से कम नजर नहीं आतीं,दूर से सायरन की आवाज आती है, लोग रास्ता छोड़ देते हैं, दुकानदार चौकन्ने हो जाते हैं और राहगीर समझते हैं कि शायद कोई बड़ी प्रशासनिक टीम या आपातकालीन वाहन गुजर रहा है,लेकिन जैसे ही गाड़ी पास आती है तो पता चलता है कि उसमें कोई जनप्रतिनिधि,नेता या उनका करीबी बैठा हुआ है,कुछ लोग तो मजाक में कहने लगे हैं कि अब गांवों में एम्बुलेंस कम और नेताजी एक्सप्रेस ज्यादा हूटर बजा रही है,ग्रामीणों का कहना है कि कुछ जनप्रतिनिधि गांवों में ऐसे प्रवेश करते हैं मानो किसी जिले का दौरा करने मंत्री या राज्यपाल आ रहे हों,गाड़ी में हूटर,आगे व्हीआईपी स्टिकर,पीछे पदनाम और चेहरे पर ऐसा भाव जैसे पूरा प्रशासन उन्हीं के इशारे पर चलता हो।

जनता को चाहिए सादगी,सिस्टम को चाहिए ईमानदारी

आम लोगों का कहना है कि जनता को ऐसे अधिकारी और जनप्रतिनिधि पसंद आते हैं जो सादगी से काम करें, नियमों का पालन करें और खुद उदाहरण बनें, जनता को सड़क पर सायरन नहीं, काम की आवाज सुनाई देनी चाहिए,अब देखना यह है कि प्रशासन व्हीआईपी संस्कृति पर वास्तव में लगाम लगाता है या फिर सायरन की सत्ता और पद प्रदर्शन की राजनीति यूं ही सड़कों पर दौड़ती रहेगी।

व्हीआईपी संस्कृति का ग्रामीण संस्करण

ग्रामीण इलाकों में यह व्हीआईपी संस्कृति अब नई पहचान बनती जा रही है, गांवों में यदि कोई गाड़ी बिना हूटर और स्टिकर के पहुंच जाए तो लोग शायद उसे सामान्य वाहन मान लें,लेकिन जैसे ही सायरन बजता है, लोग समझ जाते हैं कि कोई बड़ा आदमी आया है,कुछ ग्रामीणों ने तंज कसते हुए कहा कि अब गांवों में विकास कम और व्हीआईपी एंट्री ज्यादा दिखाई देती है,एक बुजुर्ग ग्रामीण ने कहा पहले नेता पैदल चलकर जनता से मिलते थे, अब जनता को पहले गाड़ी का हूटर सुनना पड़ता है,तब जाकर नेताजी उतरते हैं।

कानून की किताब और सड़क की हकीकत में बड़ा अंतर

मोटरयान अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटरयान नियमों के अनुसार निजी वाहनों में हूटर,सायरन और भ्रामक पहचान प्रतिबंधित है। नंबर प्लेट निर्धारित प्रारूप में होना अनिवार्य है, किसी भी निजी वाहन में ऐसा प्रदर्शन नहीं किया जा सकता जिससे वह विशेष श्रेणी का वाहन प्रतीत हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कह रही है। नियम किताबों में दिखाई देते हैं,जबकि सड़क पर रुतबा चलता दिखाई देता है,विशेषज्ञों का कहना है कि निजी वाहनों में पदनाम और विशेष पहचान का अत्यधिक प्रदर्शन लोकतांत्रिक सादगी के विपरीत है।

कार्रवाई की मांग,लेकिन क्या होगा असर?

अब इस पूरे मामले को लेकर कलेक्टर से शिकायत की गई है और जिलेभर में विशेष अभियान चलाने की मांग उठी है तो शिकायतकर्ताओं ने कहा है कि अवैध हूटर लगे वाहनों पर कार्रवाई हो,व्हीआईपी स्टिकर और भ्रामक बोर्ड हटाए जाएं,नंबर प्लेट नियमों का पालन कराया जाए, प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों पर भी समान नियम लागू हों, लेकिन लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कार्रवाई वास्तव में होगी या फिर शिकायत फाइलों में घूमती रह जाएगी?

सत्ता का साउंड सिस्टम या सेवा का संस्कार?

समाजशास्त्रियों का मानना है कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की पहचान उनके कार्यों से होनी चाहिए, न कि गाड़ियों में लगे हूटर और बोर्ड से। लेकिन आज स्थिति उलटी दिखाई दे रही है,काम कम और प्रदर्शन ज्यादा दिखाई देता है,कुछ लोगों का कहना है कि यदि किसी अधिकारी या नेता को अपना पद बार-बार गाड़ी पर लिखवाकर बताना पड़ रहा है,तो शायद जनता के बीच उसका प्रभाव काम से नहीं बन पा रहा।

लालबत्ती गई...मानसिकता नहीं गई...

देशभर में व्हीआईपी संस्कृति खत्म करने के नाम पर लालबत्तियां हटाई गई थीं, लेकिन अब उसी मानसिकता ने नया रूप ले लिया है, कहीं हूटर है, कहीं फ्लैशलाइट, कहीं बड़े-बड़े पदनाम, तो कहीं व्हीआईपी स्टिकर, ऐसा लगने लगा है कि लालबत्ती केवल गाड़ी से उतरी है, दिमाग से नहीं।

रेवा यादव के नेतृत्व में यादव समाज ने किया कोरिया कलेक्टर का स्वागत

सर्व यादव समाज जिला कोरिया द्वारा नवनियुक्त कलेक्टर श्रोक्तिमा यादव का किया गया अभिनंदन

-संवाददाता-
बैकुंठपुर/कोरिया,20 मई 2026 (घटती-घटना)।

सर्व यादव समाज जिला कोरिया द्वारा नवनियुक्त कलेक्टर श्रोक्तिमा यादव का आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया गया,यह स्वागत कार्यक्रम समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों और सदस्यों की उपस्थिति में आयोजित हुआ,जहां समाजजनों ने पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान किया।

कार्यक्रम का नेतृत्व समाजसेवी रेवा यादव ने किया। इस दौरान समाज के लोगों ने कलेक्टर श्रोक्तिमा यादव को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं देते हुए जिले के विकास और सामाजिक समरसता को लेकर सकारात्मक चर्चा भी की,समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि जिले को एक ऊर्जावान और संवेदनशील प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नई कलेक्टर मिली हैं, जिससे जिले के विकास कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद है,इस अवसर पर रेवा यादव ने कहा कि समाज हमेशा प्रशासन के साथ मिलकर जनहित के कार्यों में सहयोग करता रहेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि कलेक्टर श्रोक्तिमा यादव के नेतृत्व में जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य,महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बेहतर कार्य होंगे,कार्यक्रम में उपस्थित समाजजनों ने कलेक्टर का पारंपरिक तरीके से स्वागत करते हुए उन्हें सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दीं,इस दौरान सर्व यादव समाज जिला कोरिया के कई पदाधिकारी, वरिष्ठजन एवं समाज के सदस्य उपस्थित रहे।

जनजातीय गरिमा उत्सव अभियान का शुभारंभ

करहियाखाड़ में विधायक श्री भईया लाल राजवाड़े एवं कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने किया जनजागरूकता अभियान

-संवाददाता-
कोरिया,20 मई 2026 (घटती-घटना)।

जिला कोरिया के ग्राम पंचायत करहियाखड़ में मंगलवार को जनजातीय गरिमा उत्सव अभियान के अंतर्गत जागरूकता एवं जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विधायक श्री भईया लाल राजवाड़े, कलेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जनजातीय समुदायों को शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना,उनकी सांस्कृतिक विरासत एवं परंपराओं के संरक्षण को बढ़ावा देना तथा समाज में जनजातीय समुदाय के सम्मान,स्वाभिमान एवं सहभागिता को सशक्त बनाना रहा। इस अवसर पर ग्रामीणों को हितग्राही मूलक योजनाओं,शिक्षा,स्वास्थ्य,आजीविका एवं सामाजिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जनजातीय गरिमा उत्सव एवं जनभागीदारी अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विस्तृत कार्ययोजना जारी की गई है। अभियान का उद्देश्य पीएम जनमन एवं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के माध्यम

से जनजातीय समुदायों तक शासन की योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करना, व्यापक प्रचार-प्रसार करना,शिकायतों का त्वरित निराकरण करना तथा ग्राम स्तर पर जनभागीदारी को मजबूत बनाना है।

अभियान के तहत 20 मई को पीएम-जनमन एवं डीए-जगुआ अंतर्गत चयनित ग्रामों में ग्राम संपर्क गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इस दौरान अधिकारी,कर्मयोगी एवं गैर शासकीय संगठनों के प्रतिनिधि गांवों में पैदल भ्रमण कर वास्तविक स्थिति का अवलोकन करेंगे। साथ ही ग्रामीणों को शासन की योजनाओं के प्रति जागरूक कर जनसुनवाई की तिथि की जानकारी देंगे। 21 से 23 मई तक चयनित ग्रामों एवं सेवा केंद्रों में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे,जहां शिकायतों के त्वरित निराकरण, अधिकारों के संरक्षण एवं समस्याओं के समाधान हेतु प्रतिदिन गतिविधियां संचालित होंगी।

अभियान के दौरान ग्राम स्तर पर प्रतिदिन संतृप्ति शिविर एवं स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में पात्र हितग्राहियों को आधार कार्ड,आयुष्मान कार्ड, मातृ वंदन योजना,जनधन खाता,जाति प्रमाण पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड,उज्ज्वला योजना सहित विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। 24 मई को अभियान के अंतर्गत किए गए कार्यों का अभिलेखीकरण किया जाएगा,जबकि 25 मई को समीक्षा एवं ब्रीफिंग कार्यक्रम आयोजित होगा। इसमें जनसुनवाई से संबंधित प्रगति रिपोर्ट तैयार की जाएगी,जिसमें प्राप्त शिकायतें, निराकृत प्रकरण,लंबित मामले,जिम्मेदार अधिकारी एवं कार्रवाई की तिथि जैसी जानकारियां शामिल होंगी। अभियान के समापन के बाद कलेक्टर एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास द्वारा अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित कर आगामी रणनीति पर चर्चा की जाएगी।

जनप्रतिनिधि या अघोषित ठेकेदार?

पोड़ी बचरा स्वास्थ्य केंद्र निर्माण में भ्रष्टचार के आरोप

11 लाख के स्वास्थ्य भवन में घटिया निर्माण! ग्रामीणों ने खोली अनियमितताओं की पोल

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण बना कमाई का जरिया? मानकों की उड़ रही धज्जियां

पोडी बचरा स्वास्थ्य केंद्र निर्माण में बड़ा खेल! घटिया सामग्री और मिलीभगत के आरोप

खनिज न्यास की राशि पर सवाल, स्वास्थ्य केंद्र निर्माण में गुणवत्ता से समझौता

जनपद उपाध्यक्ष पर ठेकेदारी के आरोप, स्वास्थ्य केंद्र निर्माण में धांधली से ग्रामीण नाराज़

ईंट हाथ लगाते ही टूट रही, गिट्टी भी मानक विहीन! स्वास्थ्य भवन निर्माण पर उठे सवाल

11 लाख का निर्माण, लेकिन सुरक्षा और गुणवत्ता दोनों गायब

स्वास्थ्य केंद्र निर्माण में भ्रष्टाचार की बू- मजदूर बिना सुरक्षा, भवन बिना गुणवत्ता

-राजेन्द्र शर्मा-

खड़गवां/पोड़ी बचरा,20 मई 2026 (घटती-घटना)।

स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से पोड़ी बचरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वीकृत अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य अब गंभीर सवालों के घेरे में आ गया है, खनिज न्यास मद से लगभग 11 लाख 32 हजार रुपये की लागत से बनने वाले इस अतिरिक्त कक्ष के निर्माण में भारी अनियमितता, घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग,गुणवत्ता से समझौता और नियम विरुद्ध तरीके से कार्य कराए जाने के आरोप सामने आए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पूरा निर्माण कार्य एक जनप्रतिनिधि के संरक्षण में अघोषित ठेकेदारी के रूप में संचालित हो रहा है, जिससे शासन की राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है, ग्रामीणों के अनुसार यह निर्माण कार्य मार्च 2026 तक पूर्ण होना था,लेकिन लंबे समय तक कार्य प्रारंभ ही नहीं किया गया। बाद में पंचायत प्रतिनिधियों पर दबाव और भुगतान प्रक्रिया पूरी होने के बाद जल्दबाजी में निर्माण कार्य शुरू किया गया, जिसमें गुणवत्ता और तकनीकी मानकों की पूरी तरह अनदेखी की जा रही है।

जनप्रतिनिधि पर ठेकेदारी करने का आरोप

मामले में सबसे गंभीर आरोप यह है कि बैकुंठपुर जनपद पंचायत उपाध्यक्ष स्वयं निर्माण कार्य को प्रभावित कर रहे हैं और अप्रत्यक्ष रूप से ठेकेदार की भूमिका निभा रहे हैं, ग्रामीणों का कहना है कि नियमों के अनुसार जनप्रतिनिधि निर्माण कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से ठेकेदारी नहीं कर सकते,लेकिन यहां प्रभाव और पहुंच का उपयोग कर निर्माण कार्य को नियंत्रित किया जा रहा है,स्थानीय लोगों का आरोप है कि पंचायत के सरपंच और सचिव को दबाव में लेकर निर्माण सामग्री सप्लायर प्रियांश ट्रेडर्स के नाम लगभग 3 लाख 99 हजार रुपये की राशि आहरित करवाई गई। भुगतान होने के बावजूद निर्माण कार्य लंबे समय तक अधूरा पड़ा रहा, जिससे पंचायत प्रतिनिधि भी परेशान हो गए थे,ग्रामीणों के मुताबिक जब लगातार दबाव बढ़ा और सवाल उठने लगे तब जाकर निर्माण कार्य शुरू किया गया, लेकिन उसमें भी गुणवत्ता की खुली अनदेखी शुरू हो गई।

निर्माण स्थल पर मानकों की खुलेआम अनदेखी

निर्माण स्थल पर उपयोग हो रही सामग्री को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं,उनका कहना है कि भवन के कॉलम निर्माण में जहां 20 एमएम गिट्टी का उपयोग होना चाहिए,वहां 30 से 40 एमएम आकार की बड़ी गिट्टी डाली जा रही है। तकनीकी जानकारों के अनुसार गलत आकार की गिट्टी उपयोग करने से कॉलम की मजबूती प्रभावित होती है और भविष्य में भवन कमजोर पड़ सकता है,ग्रामीणों ने निर्माण में उपयोग हो रही ईंटों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ईंटें इतनी कमजोर हैं कि हाथ लगाने और हल्का दबाव पड़ते ही टूट जा रही हैं। इससे यह आशंका और गहरी हो गई है कि निर्माण कार्य केवल खानापूर्ति के उद्देश्य से किया जा रहा है,इतना ही नहीं, पीसीसी कार्य में भी निर्धारित अनुपात का पालन नहीं किया जा रहा, ग्रामीणों के अनुसार केवल गिट्टी और सीमेंट डालकर काम पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि मिश्रण में आवश्यक गुणवत्ता नहीं दिखाई दे रही।

मिक्सर मशीन की जगह बेलचा-फावड़े से हो रहा मिश्रण

ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि निर्माण कार्य में आधुनिक मिक्सर मशीन का उपयोग नहीं किया जा रहा, मजदूर हाथों से बेलचा और फावड़े के माध्यम से सीमेंट, रेत और गिट्टी का मिश्रण तैयार कर रहे हैं। इससे सामग्री का सही अनुपात नहीं बन पाता और निर्माण की मजबूती प्रभावित होती है, स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि करोड़ों रुपये की सरकारी योजनाओं में इसी प्रकार काम होगा तो सरकारी भवन कुछ ही वर्षों में जर्जर हो जाएंगे। लोगों ने इसे शासन की राशि का खुला दुरुपयोग बताया है।

सरिया की गुणवत्ता पर भी उठे सवाल

ग्रामीणों ने निर्माण में उपयोग किए जा रहे सरिया की गुणवत्ता को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं, लोगों का कहना है कि सरिया पतला और कमजोर दिखाई दे रहा है, जिससे भवन की दीर्घकालिक मजबूती संदिग्ध हो गई है, ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण एजेंसी द्वारा हर स्तर पर लागत बचाने की कोशिश की जा रही है, ताकि अधिक से अधिक राशि बचाकर निजी लाभ कमाया जा सके।

इंजीनियर और विभागीय अधिकारियों की चुप्पी से बढ़े संदेह-

ग्रामीणों ने विभागीय इंजीनियर और एसडीओ की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं, उनका कहना है कि निर्माण स्थल पर न तो इंजीनियर निरीक्षण करने पहुंचते हैं और न ही किसी प्रकार की तकनीकी निगरानी दिखाई देती है, स्थानीय लोगों के अनुसार निर्माण कार्य समय पर शुरू हुआ या नहीं, इसका भी कोई परीक्षण नहीं किया गया। यही कारण है कि ठेकेदार खुलेआम नियमों और गुणवत्ता मानकों की अनदेखी कर रहा है, ग्रामीणों का कहना है कि यदि विभागीय अधिकारी समय-समय पर निरीक्षण करते और गुणवत्ता की जांच कराते, तो इस प्रकार की लापरवाही सामने नहीं आती।

ग्रामीणों ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग

ग्रामीणों ने जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और खनिज न्यास समिति से मांग की है कि निर्माण कार्य की निष्पक्ष जांच कराई जाए, साथ ही निर्माण कार्य में उपयोग हो रही सामग्री की लैब जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, लोगों ने यह भी मांग की कि जब तक गुणवत्ता की जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक निर्माण कार्य पर रोक लगाई जाए।

मामले की शिकायत मुझे भी मिली है। मैं स्वयं जाकर निर्माण कार्य का निरीक्षण करूंगा। निरीक्षण में जो भी कमियां पाई जाएंगी, उनमें सुधार कराया जाएगा तथा निर्माण कार्य कराने वाले के खिलाफ उचित कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा।

— भानप्रताप सिंह

मजदूरों की सुरक्षा के नाम पर शून्य व्यवस्था

निर्माण कार्य में लगे मजदूरों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी गंभीर लापरवाही सामने आई है,मौके पर काम कर रहे मजदूर बिना हेलमेट,सेफ्टी शूज और अन्य सुरक्षा उपकरणों के कार्य करते दिखाई दे रहे हैं,ग्रामीणों ने कहा कि निर्माण कार्य के दौरान किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है,लेकिन न तो ठेकेदार और न ही विभागीय अधिकारी मजदूरों की सुरक्षा को लेकर गंभीर दिखाई दे रहे हैं,विशेषज्ञों के अनुसार निर्माण कार्य में सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराना अनिवार्य होता है, लेकिन यहां सुरक्षा मानकों को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है।

ऊपर से नीचे तक मिलीभगत का आरोप

ग्रामीणों का आरोप है कि इस पूरे मामले में ऊपर से नीचे तक मिलीभगत होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं हो रही,लोगों का कहना है कि 11 लाख से अधिक की राशि स्वीकृत होने के बावजूद यदि घटिया निर्माण हो रहा है तो यह स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है,ग्रामीणों ने पूरे निर्माण कार्य की तकनीकी जांच कराने, उपयोग की गई सामग्री का गुणवत्ता परीक्षण करवाने तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

स्वास्थ्य केंद्र भवन की गुणवत्ता पर उठी चिंता

स्थानीय लोगों ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्र के लोगों के लिए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुविधा केंद्र है,यदि यहां बनने वाला अतिरिक्त कक्ष ही कमजोर और घटिया गुणवत्ता का होगा तो भविष्य में मरीजों, डॉक्टरों और कर्मचारियों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है,ग्रामीणों का कहना है कि शासन लाखों रुपये इसलिए खर्च करता है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकें,लेकिन भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के कारण योजनाओं का उद्देश्य ही खत्म हो जाता है।

छत्तीसगढ़ भगवान श्रीराम का ननिहाल, यहां के लोग राम के मामा - जगद्गुरु रामभद्राचार्य

श्रीराम कथा के तीसरे दिन माता कौशल्या जन्म प्रसंग सुन भावविभोर हुए श्रद्धालु, जय श्रीराम के जयघोष से गूंजा चिरमिरी

भक्ति रस में डूबा कथा पंडाल

श्रीराम कथा के तीसरे दिन सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ कथा स्थल पर उमड़ने लगी थी। महिलाओं,युवाओं, बुजुर्गों और बच्चों सहित हजारों की संख्या में श्रद्धालु कथा श्रवण के लिए पहुंचे, कथा स्थल पर बैठने की व्यवस्था पूरी तरह भर गई और देर से पहुंचने वाले श्रद्धालु बाहर खड़े होकर कथा सुनते नजर आए,पूरे आयोजन स्थल को आकर्षक धार्मिक सजावट से सजाया गया था। मंच पर भगवान श्रीराम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की भव्य झांकी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी रही। कथा के दौरान भजन-कीर्तन और संगीतमय प्रस्तुतियों ने वातावरण को और अधिक भक्तिमय बना दिया।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने लिया आशीर्वाद

आज की कथा में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल अपनी धर्मपत्नी कांति जायसवाल के साथ पहुंचे,उन्होंने जगद्गुरु रामभद्राचार्य महाराज का आशीर्वाद प्राप्त कर कथा श्रवण किया, इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन समाज को सकारात्मक दिशा देने का कार्य करते हैं और रामकथा भारतीय संस्कृति और मूल्यों को मजबूत करने का माध्यम है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री सहित कई जनप्रतिनिधि रहे मौजूद

श्रीराम कथा में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े भी शामिल हुईं। उन्होंने कथा श्रवण कर प्रदेश और क्षेत्र की सुख-समृद्धि की कामना की, इसके अलावा भाजपा के कई जनप्रतिनिधि,स्थानीय नेता,सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिक भी कथा में उपस्थित रहे, कथा स्थल पर नेताओं और श्रद्धालुओं का एक साथ धार्मिक वातावरण में शामिल होना आयोजन की विशेषता बन गया।

-रवि सिंह-

चिरमिरी/एमसीबी,20 मई 2026 (घटती-घटना)।

चिरमिरी में आयोजित भव्य श्रीराम कथा के तीसरे दिन श्रद्धा,भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत संगम देखने को मिला। कथा पंडाल में हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति के बीच जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज ने माता कौशल्या के जन्म प्रसंग का अत्यंत मार्मिक और भावपूर्ण वर्णन किया,उनके श्रीमुख से निकली रामकथा ने श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया और पूरा वातावरण जय श्रीराम के जयघोष से गूंज उठा,कथा के दौरान स्वामी रामभद्राचार्य महाराज ने कहा कि माता कौशल्या का जन्म छत्तीसगढ़ की पवित्र धरती पर हुआ था, इसलिए छत्तीसगढ़ भगवान श्रीराम का ननिहाल है। उन्होंने श्रद्धालुओं से कहा कि इस दृष्टि से यहां के लोग भगवान श्रीराम के मामा कहलाते हैं। यह बात सुनते ही कथा पंडाल तालियों और जयकारों से गूंज उठा।

राम से विशेष जुड़ी है छत्तीसगढ़ की धरती

जगद्गुरु रामभद्राचार्य महाराज ने अपने प्रवचन में कहा कि छत्तीसगढ़ केवल प्राकृतिक सौंदर्य और संस्कृति की भूमि ही नहीं,बल्कि भगवान श्रीराम की स्मृतियों और आध्यात्मिक विरासत से जुड़ी पावन धरा है,उन्होंने कहा कि वनवास काल में भगवान श्रीराम ने छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों में समय बिताया था और यहां की धरती आज भी राममय संस्कृति को अपने भीतर समेटे हुए है, उन्होंने माता कौशल्या के जीवन,त्याग और मातृत्व का वर्णन करते हुए कहा कि माता कौशल्या केवल अयोध्या की महारानी नहीं थीं, बल्कि सनातन संस्कृति की आदर्श माता थीं। उनके संस्कारों ने ही भगवान श्रीराम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम को जन्म दिया,कथा के दौरान महाराज ने जैसे ही माता कौशल्या जन्म प्रसंग का उल्लेख किया,श्रद्धालुओं में भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा,कई श्रद्धालु भक्ति में डूबे नजर आए,वहीं पूरे पंडाल में लगातार सियावर रामचंद्र की जय और जय श्रीराम के जयघोष गूंजते रहे।

रामकथा केवल धार्मिक आयोजन नहीं,संस्कारों की पाठशाला

अपने प्रवचन में जगद्गुरु रामभद्राचार्य महाराज ने कहा कि रामकथा केवल धार्मिक आयोजन नहीं है,बल्कि यह जीवन को सही दिशा देने वाली संस्कारों की पाठशाला है,उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम का जीवन त्याग, मर्यादा, सेवा और आदर्शों का प्रतीक है,जिससे हर व्यक्ति को सीख लेने की आवश्यकता है, उन्होंने युवाओं से भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा से जुड़े रहने का आह्वान करते हुए कहा कि रामकथा समाज को जोड़ने और नैतिक मूल्यों को मजबूत करने का सबसे बड़ा माध्यम है।

राममय हुआ चिरमिरी शहर

श्रीराम कथा के आयोजन से पूरा चिरमिरी क्षेत्र इन दिनों राममय दिखाई दे रहा है। शहर में जगह-जगह भगवान श्रीराम के पोस्टर,भगवा ध्वज और स्वागत द्वार लगाए गए हैं। कथा स्थल तक पहुंचने वाले मार्गों को भी विशेष रूप से सजाया गया है, आयोजन समिति द्वारा श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, प्रसाद, बैठने और पार्किंग की विशेष व्यवस्था की गई है। बड़ी संख्या में स्वयंसेवक व्यवस्था संभालते नजर आए।

आगामी दिनों में और बढ़ेगी श्रद्धालुओं की भीड़

आयोजन समिति के सदस्यों के अनुसार आगामी दिनों में कथा में श्रद्धालुओं की संख्या और अधिक बढ़ने की संभावना है, दूर-दराज क्षेत्रों से भी लोग कथा श्रवण के लिए चिरमिरी पहुंच रहे हैं, शहरवासियों का कहना है कि लंबे समय बाद चिरमिरी में इतना बड़ा धार्मिक आयोजन हो रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक माहौल बना हुआ है।

CMYK

रेवती रमण मिश्र पीजी कॉलेज बना 'लू परीक्षा केंद्र'!

तपती सड़कें और खुला कॉलेज,आखिर छात्रों की जिंदगी इतनी सस्ती क्यों?

'डिग्री चाहिए तो लू सहो' सूरजपुर कॉलेज की व्यवस्था पर उठे सवाल
गर्मी से बचने की एडवाइजरी जारी,मगर कॉलेजों में जारी अग्निपरीक्षा

- छात्र धूप में झुलसे...जिम्मेदार ठंडी हवा में व्यस्त,कॉलेज खुला है...क्योंकि छात्रों को अभी और तपना बाकी है...
- स्कूल बंद, कोर्ट बंद...मगर कॉलेज खुले हैं क्योंकि छात्र शायद ऊंट की नस्ल के हैं...
- 42 से 45 डिग्री की आग बरसाती गर्मी में सरगुजा विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों का अनोखा प्रयोग

42 से 45 डिग्री में कॉलेज संचालन पढ़ाई कम, सहनशक्ति टेस्ट ज्यादा
सरगुजा विश्वविद्यालय का नया मॉडल में लू सहने वाला ही बनेगा ग्रेजुएट!

ओंकार पाण्डेय

सूरजपुर 20 मई 2026 (घटती-घटना)। प्रदेश में इस समय भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, सड़कें तवे की तरह तप रही हैं और दोपहर में बाहर निकलना किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं, सरकार ने स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया है, कोर्ट तक में छुट्टियां चल रही हैं, स्वास्थ्य विभाग लगातार लू से बचने की एडवाइजरी जारी कर रहा है, लेकिन सरगुजा विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित रेवती रमण मिश्र शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सूरजपुर में शायद मौसम विभाग की चेतावनी नहीं पहुंची, यहां छात्र-छात्राओं को रोज तपती धूप में कॉलेज आने-जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, वायरल हो रही तस्वीरें इस पूरी व्यवस्था की संवेदनहीनता को उजागर कर रही हैं, तस्वीरों में छात्र-छात्राएं सड़क किनारे धूप से बचने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं, कोई पेड़ की छांव ढूंढ रहा है, कोई स्कूटी के पास खड़ा होकर राहत लेने की कोशिश कर रहा है, चेहरों पर गर्मी की थकान साफ दिखाई दे रही है।

बता दे की देश बदल रहा है,व्यवस्था बदल रही है,शिक्षा का स्तर बदल रहा है और अब लगता है कि विद्यार्थियों की सहनशक्ति की भी सरकारी टेस्टिंग शुरू हो चुकी है, प्रदेश में तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच झूल रहा है, सड़कें ऐसी तप रही हैं मानो किसी ने धरती को तंदूर पर रख दिया हो,लोग दोपहर में घर से निकलने से बच रहे हैं,लेकिन सरगुजा विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयों ने शायद विज्ञान और मानव शरीर की सीमाओं को चुनौती देने का ठेका ले रखा है, यहां कॉलेज नियमित रूप से संचालित हो रहे हैं, सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर तक क्लासें चल रही हैं, यानी ठीक उसी समय जब सूरज देवता अपना सबसे खतरनाक रूप दिखाते हैं,

सरकारी संवेदनशीलता का नया मॉडल में छोटे बच्चों को बचाओ, बड़े खुद बच जाएं तो ठीक-

सरकार ने स्कूलों को बंद कर दिया क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, कोर्ट में अवकाश हो गया क्योंकि न्यायाधीशों को भी इंसानी शरीर मिला है, सरकारी दफ्तरों में एसी और कूलर की व्यवस्था है क्योंकि अधिकारी भी पसीना पसंद नहीं करते, लेकिन कॉलेजों के मामले में शायद यह सोच लागू की गई है कि डिग्री चाहिए तो तपस्या करनी पड़ेगी, अब सवाल यह है कि आखिर महाविद्यालयीन छात्र किस श्रेणी में आते हैं? क्या वे इंसान नहीं हैं? क्या उनकी तबीयत खराब नहीं हो सकती? क्या उन्हें लू नहीं लगती? या फिर विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोई नया मेडिकल रिसर्च कर लिया है कि 18 साल के बाद शरीर में गर्मी-रोधी क्षमता स्वत: विकसित हो जाती है?

लगता है विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह मान लिया है कि कॉलेज के छात्र-छात्राएं सामान्य मनुष्य नहीं बल्कि रेगिस्तान में चलने वाले ऊंट हैं, जिन्हें न गर्मी लगती है, न प्यास और न ही लू का असर होता है।

सुबह कॉलेज जाओ, दोपहर में लौटो...बीच में जिंदगी बची रही तो पढ़ाई भी कर लो...

सूरजपुर जिले सहित सरगुजा संभाग के कई ग्रामीण इलाकों से छात्र-छात्राएं कॉलेज पहुंचते हैं, कई छात्र बस सुविधा के अभाव में पैदल या निजी साधनों से लंबी दूरी तय करते हैं, सुबह बैग टांगे छात्र जब घर से निकलते हैं तो मां-बाप की नजर पहले आसमान पर जाती है, फिर बच्चे पर, क्योंकि आजकल कॉलेज जाना पढ़ाई कम और 'लू सर्वाइवल मिशन' ज्यादा लगता है, दोपहर में लौटते समय सड़कें इतनी गर्म होती हैं कि चप्पल तक जवाब दे जाए। गर्म हवा ऐसी चलती है मानो किसी ने हेयर ड्रायर को फुल स्पीड पर चालू कर दिया हो,कई छात्रों ने बताया कि कॉलेज पहुंचते-पहुंचते सिर दर्द, चक्कर, उल्टी और शरीर में पानी की कमी जैसी समस्याएं होने लगती हैं, लेकिन व्यवस्था को इससे क्या फर्क पड़ता है? व्यवस्था का मूल सिद्धांत है जब तक छात्र बेहोश होकर वायरल न हो जाए,तब तक सब सामान्य है।

कॉलेजों में पढ़ाई कम, गर्मी की प्रैक्टिकल ज्यादा

छात्रों का कहना है कि इस समय कॉलेजों में पढ़ाई की स्थिति भी किसी मजाक से कम नहीं है, एक छात्र ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कई टीचर समय पर नहीं आते, जब मन हुआ तब क्लास ले ली, नहीं तो स्टाफ रूम में बैठकर मोबाइल चलाया और चले गए। लेकिन छात्रों की उपस्थिति जरूर जरूरी है, यानी छात्र धूप में जलते हुए कॉलेज पहुंचें, लेकिन शिक्षक महोदय का मूड हुआ तभी शिक्षा का दर्शन होगा,अब इसे शिक्षा व्यवस्था कहें या 'मनोरंजन आधारित शिक्षण प्रणाली',यह समझना मुश्किल है।

एसी में शिक्षा नीति,गर्मी में छात्र नीति

कॉलेजों में सबसे दिलचस्प दृश्य तब देखने को मिलता है जब छात्र पसीने से भीगे क्लासरूम में बैठे होते हैं और दूसरी तरफ स्टाफ रूम में कूलर-एसी की ठंडी हवा चल रही होती है, छात्रों के लिए पंखा भी कई बार भगवान भरोसे चलता है, कहीं कूलर खराब है, कहीं पानी नहीं है, कहीं बिजली गायब है, लेकिन अधिकारियों और शिक्षकों के कमरों में व्यवस्था ऐसी रहती है कि मानो वहां गर्मी का प्रवेश प्रतिबंधित हो यानी गर्मी सिर्फ विद्यार्थियों के लिए है, बाकी लोग प्रशासनिक प्राणी हैं।

क्या विश्वविद्यालय ने 'लू सहनशक्ति प्रतियोगिता' शुरू कर दी है?

जिस समय स्वास्थ्य विभाग लोगों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दे रहा है, उसी समय कॉलेजों में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जा रही है, अब छात्र पढ़ाई कम और यह सोचकर ज्यादा परेशान हैं कि आज लौटते समय चक्कर आएगा या नहीं? पानी खत्म हुआ तो क्या होगा? बस छूट गई तो धूप में कैसे जाएंगे? ऐसा लग रहा है कि सरगुजा विश्वविद्यालय ने पढ़ाई के साथ-साथ 'लू सहनशक्ति प्रतियोगिता' भी शुरू कर दी है,जो छात्र 45 डिग्री तापमान में रोज कॉलेज आकर जीवित लौट आएगा,वही असली डिग्री का हकदार माना जाएगा।

ग्रामीण छात्रों की परेशानी सबसे ज्यादा

ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले छात्रों की हालत और खराब है,कई गांवों से कॉलेज तक सीधी बस सुविधा नहीं है,छात्र पहले ऑटो पकड़ते हैं,फिर बस, फिर पैदल कॉलेज पहुंचते हैं,दोपहर में वापस लौटते समय सड़कें वीरान हो जाती हैं क्योंकि सामान्य लोग उस समय बाहर निकलना ही नहीं चाहते,लेकिन छात्र मजबूरी में निकलते हैं,अभिभावकों का कहना है कि बच्चों की तबीयत लगातार खराब हो रही है,लेकिन कॉलेज प्रशासन को इसकी कोई चिंता नहीं दिख रही।

संवेदनशीलता सिर्फ भाषणों में?

सरकार मंचों से छात्रहित की बड़ी-बड़ी बातें करती है,युवाओं को देश का भविष्य बताया जाता है, शिक्षा को प्राथमिकता कहा जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि वही भविष्य आज धूप में झुलस रहा है, यदि इतनी भीषण गर्मी में स्कूल बंद हो सकते हैं,तो महाविद्यालयों में वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती? ऑनलाइन क्लास,समय परिवर्तन या अस्थायी अवकाश जैसे विकल्पों पर विचार क्यों नहीं किया जा रहा?

कहीं ऐसा न हो कि आदेश तब निकले जब कोई बड़ी घटना हो जाए...

प्रशासन की कार्यशैली अक्सर ऐसी रही है कि पहले घटना होती है, फिर जांच बैठती है,फिर आदेश निकलते हैं, डर इस बात का है कि कहीं किसी छात्र की हालत गंभीर होने या किसी अप्रिय घटना के बाद ही व्यवस्था की नींद न खुले, क्योंकि यहां अक्सर नियम घटना के बाद बनते हैं, पहले नहीं।

छात्रों की मांग : पढ़ाई चाहिए,लेकिन जिंदगी दांव पर नहीं, छात्रों और अभिभावकों ने मांग की है कि...

- भीषण गर्मी को देखते हुए महाविद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया जाए।
- कॉलेज का समय सुबह जल्दी किया जाए।
- सभी क्लासरूम में पंखा,कूलर और पेयजल की व्यवस्था अनिवार्य हो।
- शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाए।

अंतिम सवाल

जब अधिकारी खुद दोपहर की धूप में पांच मिनट खड़े नहीं हो सकते,जब सरकारी दफ्तर बिना एसी-कूलर के नहीं चल सकते, जब स्कूलों को गर्मी के कारण बंद किया जा सकता है,तो फिर कॉलेज के छात्रों को इस आग उगलती गर्मी में रोज सड़क पर क्यों उतारा जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि व्यवस्था ने मान लिया है- 'विद्यार्थी हैं... झेल लेंगे। '

मनोरंजन समाचार

महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बात जरूरी : सबा आजाद

जल्द ही अभिनेत्री सबा आजाद कॉमेडी-ड्रामा सीरीज हूज योर गायनिक सीजन 2 में नजर आएगी। अपकमिंग सीजन को लेकर अभिनेत्री का कहना है कि शो का मुख्य उद्देश्य उन विषयों पर खुलकर चर्चा करना है, जिन्हें समाज में अक्सर बंद कमरों तक सीमित कर दिया जाता है। इस सीरीज में वह 'डॉ. विदुषी कोठारी' का किरदार निभा रही हैं। चर्चा के दौरान सबा आजाद ने कहा कि पहले सीजन में सेक्स एजुकेशन और महिलाओं के स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया गया था। उनके मुताबिक दूसरा सीजन भी उसी सोच और उद्देश्य को आगे बढ़ाएगा।

अभिनेत्री का मानना है कि समाज में इन विषयों पर खुली चर्चा होना बेहद जरूरी है, ताकि लोगों के बीच जागरूकता बढ़ सके और महिलाओं से जुड़े मुद्दों को सामान्य नजरिए से देखा जा सके। जब सबा से पूछा गया कि क्या आज भी समाज के लिए एक स्वतंत्र और महत्वाकांक्षी महिला को स्वीकार करना कठिन है, तो उन्होंने साफ कहा कि बड़े शहरों में रहने के बावजूद जमीनी स्तर पर समाज अब भी काफी हद तक पितृसत्तात्मक सोच से प्रभावित है। अभिनेत्री ने कहा कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर सम्मान पाने के लिए आज भी अधिक मेहनत करनी पड़ती है और उनके फैसलों को लेकर समाज बहुत जल्दी राय बना लेता है।

सबा आजाद के अनुसार सामाजिक व्यवस्था लंबे समय से पुरुषों की सफलता को केंद्र में रखकर बनाई गई है। उन्होंने कहा कि देश के कई हिस्सों में आज भी महिलाओं को अपनी पसंद से काम करने या जीवन के फैसले लेने की पूरी स्वतंत्रता नहीं मिल पाती। अभिनेत्री का मानना है कि शहरों में रहने वाले लोगों को यह वास्तविकता हमेशा नजर नहीं आती, लेकिन यह सच्चाई आज भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को पेशेवर जीवन और निजी जिंदगी दोनों जगह लगातार खुद को साबित करना पड़ता है। अगर कोई महिला काम करती है, तो उसके फैसलों पर सवाल उठाए जाते हैं और अगर वह काम नहीं करती, तब भी समाज उसे जज करने से पीछे नहीं हटता।

सबा का कहना है कि यही दोहरा रवैया महिलाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। अभिनेत्री ने यह भी कहा कि कई लड़कों की परवरिश ऐसे माहौल में होती है, जहां उन्हें यह महसूस कराया जाता है कि वे महिलाओं से बेहतर हैं। ऐसे में जब उनका सामना किसी आत्मनिर्भर और मजबूत सोच वाली महिला से होता है, तो उनके अहंकार को ठेस पहुंचती है। सबा के मुताबिक कई पुरुष महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने के आदी नहीं होते, जिसकी वजह से रिश्तों में तनाव और असहजता पैदा होने लगती है।

विनीत सिंह बोले...मेरे रोल को 'धुरंधर' का बड़े साहब कहा जा रहा, ऊपरवाला देता है तो छप्पर फाड़कर देता है

आग में तपकर ही सोना कुंदन बनता है। एक जमाने में विनीत कुमार ने चाहे जितना भी संघर्ष किया हो, मगर आज उन्हें अपने संघर्ष, मेहनत और प्रतिभा का फल मिल रहा है। बीता साल उनके लिए बहुत ही मुफीद रहा। पिछले साल उनकी 8 फिल्में रिलीज हुईं और उन फिल्मों में 'छावा', 'निशानची', 'सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव' जैसी फिल्मों में उन्हें खूब तारीफ भी मिली। विनीत इन दिनों ग्वालियर में अपनी अपकमिंग फिल्म 'शक्ति शालिनी' की शूटिंग कर रहे हैं। सभी जानते हैं कि गर्मी ने पूरे देशभर में हाहाकार मचा कर रखा हुआ है और ग्वालियर में भी खूब पारा चढ़ा हुआ है। ऐसे में विनीत हीट को बीट करने के तमाम तरीके अपना रहे हैं।

सतू और सब्जा जैसे घरेलू नुस्खों से गर्मी को राहत

वे कहते हैं, 'गर्मी के मारे तो हमारा बुरा हाल है। हाल ही में तापमान 44 डिग्री था, ऐसे में शूटिंग करना आसान नहीं होता। हां, बीच में एक दिन ईश्वर की कृपा से बारिश हो गई थी और कुछ ठंडक भी, मगर फिर वही गर्मी का प्रकोप। यहां सुबह और शाम अच्छी होती है, मगर दोपहर तो आग ही उगलती है। ऐसे में मैं देसी उपाय करता हूं। सत्तू को पानी में मिलाकर उसमें जीरा और नमक डाल कर उसे पीने से बॉडी में ठंडक बनी रहती है। दूसरा घरेलू उपाय है सब्जा। यह भी काफी फायदेमंद है। इसे पानी में भिगोकर रखने के बाद साथ में कैरी किया जा सकता है। ये दो-तीन घंटे तक चलता है। ये सारे नुस्खे मैं ही नहीं बल्कि मेरा स्टाफ भी आजमाता है। जाहिर-सी बात है कि मेरी टीम ही है, जो मेरे लिए इतनी भागदौड़ करती है।' शूटिंग के दौरान होने वाली भयंकर गर्मी का एक किस्सा याद करते हुए वे कहते हैं, 'हम लोग बनारस में मुक्केबाज की शूटिंग कर रहे थे गर्मी के मौसम में टेम्प्रेचर 47 डिग्री शूटिंग की बड़ी-बड़ी हैवी लाइट्स, मैं बॉक्सिंग रिंग में दस-दस घंटे फाइट्स लड़ता था। एक दिन तो मैं एक ऐसी फाइट लड़ रहा था, जो डिजाइन नहीं थी। वो रियल फाइट थी और मैं कह सकता हूं कि वो मेरे करियर की सबसे मुश्किल शूटिंग थी। उस दिन मैंने 5 फाइट्स लड़ी थीं। आज जब भी किसी मुश्किल वेदर कंडीशन में काम करता हूं,तो खुद को मुक्केबाज की शूटिंग की याद दिलाता हूं। उससे मुझे बहुत ताकत मिलती है।'

बेटे के लिए दुनिया को बेहतर बनाना है

अपने फादरहुड के अहसास के बारे में वे कहते हैं, 'जब मैं पिता बना, तो मुझे अहसास हुआ कि हमारे माता-पिता ने हमारे लिए कितनी कुर्बानियां दी होंगी, अपनी कितनी ही रातों की नींद खराब की होगी। हर आवाज पर अलर्ट रहना पड़ा होगा। हालांकि मुझे पता हमेशा से था, मगर अहसास अब हुआ। अब लगता है कि दुनिया बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में मेरा बेटा उसी दुनिया में पलने वाला है। हालांकि वो अभी काफी छोटा है।'

पैटर्निटी लीव बढ़ाई जानी चाहिए

करियर और पर्सनल दोनों ही फ्रंट पर विनीत संतुष्ट और खुश हैं। कुछ महीने पहले वे एक प्यारे बेटे के पिता बने हैं। आज उनका बेटा 9 महीने का है। उनका मानना है कि बच्चों की देखभाल महज मां की नहीं बल्कि माता-पिता दोनों की जिम्मेदारी होती है। वे कहते हैं, 'जब से बेटा पैदा हुआ है उसने अपने बाप को काम पर लगा कर रखा है (हंसते हैं) मैं जब भी घर पर होता हूं अपने बेटे के तमाम काम खुद करता हूं। अरे, मैंने तो बेटे की पैदाइश के बाद पांच महीने तक कोई काम ही नहीं किया था। मैं पत्नी रुचिरा के अस्पताल जाने से लेकर ऑपरेशन थिएटर,डिलीवरी हर जगह उनके साथ था। आप सभी जानते ही हैं कि मैं आयुर्वेद का डॉक्टर भी हूं,तो मैं हर जगह पत्नी और बेटे के साथ रहा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक मां जब बच्चे को जन्म देती है,तो उसका पूरा सिस्टम ही जाता है। उसे कई शारीरिक, मानसिक और हार्मोनल बदलावों से गुजरना पड़ता है,ऐसे में एक बच्चे को संभालना उसके लिए आसान नहीं होता। यही वजह थी कि मैं 5 महीने तक पैटर्निटी लीव पर था। मुझे लगता है कि हमारे देश में पैटर्निटी लीव एक तो कंपल्सरी होनी चाहिए और बढ़ाई भी जानी चाहिए। अगर पिता को समय नहीं मिलेगा,तो मां पर बहुत दबाव पड़ता है। खासकर आज के समय में, जब ज्यादातर परिवार न्यूक्लियर हो गए हैं, तो दोनों की जिम्मेदारी बराबर होनी चाहिए। डिलीवरी के बाद मां को रिकवरी के लिए समय चाहिए होता है,और उस समय पिता का साथ बहुत जरूरी होता है।'

मेरे रोल को धुरंधर का बड़ा साब कहा जा रहा है...

वर्क फ्रंट पर तो विनीत कुछ ज्यादा ही मसरूफ हैं। वे कहते हैं, 'अभी मैं मध्य प्रदेश में फिल्म शक्ति शालिनी की शूटिंग कर रहा हूं। कहानी और किरदार के बारे में अभी ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। मगर इतना जरूर कहूंगा कि छावा के बाद प्रॉडक्शन हाउस के साथ यह मेरा दूसरा काम है, जो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इस फिल्म के डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार हैं, और उनके साथ काम करने में बहुत मजा आ रहा है। हम लोग ग्वालियर और उसके आसपास की रियल लोकेशन्स पर शूट कर रहे हैं। काफी इंटीरियर्स में जाकर शूट हो रहा है, जिससे फिल्म में एक ऑथेंटिक फील आएगी।' हाल ही में विनीत वेब सीरीज मटका किंग में डॉन दाऊद के छोटे -से अपीयरेंस में भी सराहे गए। चर्चा है कि 'मटका किंग पार्ट 2' में उनका काफी लंबा-चौड़ा रोल है। वे कहते हैं, 'आगे का मैं कुछ खुलासा नहीं कर सकता, मगर हां इस सीरीज में मेरी भूमिका के बाद लोग मेरे रोल की तुलना 'धुरंधर' के बड़ा साब से जरूर करने लगे हैं। मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि इस सीरीज से पहले मैं हेलो बच्चों में एक टीचर की भूमिका की थी।'

ऑनलाइन सिस्टम या ऑफलाइन सेटिंग?

ब्लड बैंक लाइसेंस में रायपुर दरबार पर उठे सवाल

जब सब ऑनलाइन है,तो मुख्यालय में भीड़ क्यों?ब्लड बैंक लाइसेंस प्रक्रिया पर बड़ा सवाल

- ब्लड बैंक लाइसेंस का खेल! ऑनलाइन प्रक्रिया के बावजूद रायपुर में क्यों लग रही लाइन ?
- ड्रग विभाग में 'ऑनलाइन' का दावा,लेकिन फाइलें चल रहीं 'ऑफलाइन' ?
- लाइसेंस के लिए पोर्टल कम, 'पहुंच' ज्यादा जरूरी ? सिस्टम पर उठे गंभीर सवाल...
- रायपुर मुख्यालय में ब्लड बैंक संचालकों की भीड़ ने बढ़ाई विभाग की मुश्किलें
- ऑनलाइन आवेदन,फिर भी मुख्यालय में हाजिरी! आखिर क्या है लाइसेंस का राज ?

-न्यूज डेस्क-

रायपुर 20 मई 2026 (घटती-घटना)। डिजिटल इंडिया, ई-गवर्नेंस और ऑनलाइन पारदर्शिता के बड़े-बड़े दावों के बीच छत्तीसगढ़ का ड्रग एंड कॉस्मेटिक विभाग इन दिनों गंभीर सवालों के घेरे में है,सवाल इसलिए,क्योंकि विभागीय नियम और पोर्टल कुछ और कहानी बताते हैं,जबकि जमीनी तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई देती है। सूत्रों से मिली जानकारी और विभागीय गतिविधियों पर नजर रखने वालों का कहना है कि प्रदेश में संचालित ब्लड बैंकों और दवा निर्माण कंपनियों से जुड़े लाइसेंस संबंधी अधिकांश कार्य पूरी तरह ऑनलाइन हैं, नए लाइसेंस जारी करना,पुराने लाइसेंस का नवीनीकरण, ओनरशिप परिवर्तन, स्थानांतरण, दस्तावेज सत्यापन और कई अन्य प्रक्रियाएं पोर्टल आधारित हैं,ऐसे में सामान्य रूप से यह माना जाना चाहिए कि आवेदकों को कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन राजधानी रायपुर स्थित मुख्यालय में पिछले कुछ समय से जिस तरह ब्लड बैंक संचालकों,एजेंटों और दवा कंपनियों के प्रतिनिधियों की लगातार भीड़ दिखाई दे रही है, उसने पूरे सिस्टम की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं,सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि जब सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है, तो फिर मुख्यालय में 'हाजिरी' लगाने की मजबूरी आखिर क्यों बन रही है?

पूरे प्रदेश में 144 ब्लड बैंक,लेकिन सवाल एक ही-भीड़ क्यों?

जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में वर्तमान में लगभग 144 ब्लड बैंक संचालित हैं, इन ब्लड बैंकों को संचालित करने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है, लाइसेंस जारी करने से लेकर उसके नवीनीकरण तक की प्रक्रिया ड्रग एंड कॉस्मेटिक विभाग के अधीन आती है, विभागीय पोर्टल और आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार आवेदन ऑनलाइन, दस्तावेज ऑनलाइन,शुल्क ऑनलाइन,ट्रैकिंग ऑनलाइन,और अधिकांश अनुमोदन भी ऑनलाइन होने चाहिए, यानी व्यवस्था ऐसी बनाई गई है कि किसी व्यक्ति को राजधानी जाकर अधिकारियों के कमरे के बाहर बैठने की आवश्यकता ही न पड़े, लेकिन सूत्र बताते हैं कि वास्तविकता इसके ठीक उलट है, राजधानी स्थित मुख्यालय में प्रतिदिन ब्लड बैंक संचालकों और उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति सामान्य बात बन चुकी है,कई बार तो घंटों तक फाइलों और आवेदन की स्थिति को लेकर लोगों को कार्यालयों के बाहर इंतजार करते देखा जाता है, अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसी कौन-सी प्रक्रिया है जो ऑनलाइन पोर्टल से पूरी नहीं हो पा रही?

क्या एजेंट संस्कृति फिर हावी हो रही है?

ऑनलाइन व्यवस्था लागू करने का सबसे बड़ा उद्देश्य था बिचौलियों और एजेंटों की भूमिका समाप्त करना,लेकिन विभागीय गलियारों में चर्चा है कि अब भी कई लोग 'काम करवाने' के नाम पर सक्रिय हैं,बताया जाता है कि कुछ प्रतिनिधि नियमित रूप से मुख्यालय में देखे जाते हैं और वे अलग-अलग संस्थानों की फाइलों की 'देखरेख' करते हैं,यदि यह सच है, तो यह सीधे-सीधे ऑनलाइन सिस्टम की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न है,क्योंकि यदि एक आवेदक को फिर भी किसी एजेंट,संपर्क या व्यक्तिगत नेटवर्क की आवश्यकता पड़ रही है, तो इसका अर्थ यही है कि व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी नहीं बन पाई है।

दवा निर्माण कंपनियों में भी वही कहानी?

मामला सिर्फ ब्लड बैंकों तक सीमित नहीं बताया जा रहा, जानकारी के अनुसार प्रदेश में करीब 69 दवा निर्माण कंपनियां भी संचालित हैं और उनका लाइसेंसिंग कार्य भी इसी विभाग के अधीन आता है,दवा निर्माण कंपनियों के लिए भी निर्माण लाइसेंस,नवीनीकरण,निरीक्षण,उत्पाद अनुमोदन,और तकनीकी दस्तावेजों की प्रक्रिया बड़े स्तर पर ऑनलाइन होती है,फिर भी यदि कंपनियों के प्रतिनिधियों की लगातार मुख्यालय में मौजूदगी बनी रहती है,तो सवाल उठना स्वाभाविक है,क्या वहां भी फाइलों को आगे बढ़ाने के लिए 'व्यक्तिगत उपस्थिति' जरूरी हो जाती है? क्या ऑनलाइन सिस्टम सिर्फ दस्तावेज अपलोड करने तक सीमित रह गया है? क्या अंतिम निर्णय अब भी 'कमरे के भीतर' ही तय होते हैं? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आम जनता भी जानना चाहती है।

लाइसेंस अथॉरिटी बदलते ही क्यों बढ़ गई आवाजाही?-

सूत्रों के अनुसार जब से प्रदेश में लाइसेंस अथॉरिटी के रूप में बेनीराम साहू की भूमिका मजबूत हुई है, तब से मुख्यालय में आने-जाने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है, हालांकि विभाग की ओर से इसे सामान्य प्रशासनिक गतिविधि बताया जा सकता है, लेकिन विभागीय हलकों में कई तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं, कुछ लोग इसे 'सिस्टम की मजबूरी' बताते हैं, तो कुछ 'सेटिंग संस्कृति' का हिस्सा मान रहे हैं, कई संचालकों का कहना है कि ऑनलाइन आवेदन के बाद भी फाइल को 'गति' देने के लिए व्यक्तिगत संपर्क जरूरी हो जाता है, कोई दस्तावेज की कमी बताता है, कोई निरीक्षण रिपोर्ट अटकने की बात करता है, तो कोई तकनीकी कारणों का हवाला देता है, यहीं से संदेह की शुरुआत होती है, यदि सब कुछ तय नियम और पोर्टल के अनुसार होना है, तो फिर फाइलें 'मुलाकात' के बाद ही आगे क्यों बढ़ती दिखाई देती हैं?

50 लाख से 1 करोड़ तक का निवेश, फिर शुरू होता है 'मैनेजमेंट'?-

ब्लड बैंक संचालन कोई छोटा व्यवसाय नहीं माना जाता, सूत्रों का दावा है कि एक ब्लड बैंक स्थापित करने में 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का खर्च आता है, भवन, मशीनें, स्टाफ, कोल्ड स्टोरेज, लैब और अन्य तकनीकी मानकों को पूरा करना पड़ता है, इतना बड़ा निवेश करने के बाद संचालकों की पहली प्राथमिकता लाइसेंस प्राप्त करना होती है, इसी बिंदु पर सबसे गंभीर आरोप सामने आते हैं, चर्चा यह है कि लाइसेंस प्रक्रिया में फाइलों को तेजी से आगे बढ़ाने, निरीक्षण को अनुकूल बनाने या लंबित मामलों को निपटाने के लिए 'अनौपचारिक व्यवस्थाएं' करनी पड़ती हैं, हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लगातार मुख्यालय में दिखाई देने वाली भीड़ ने इन चर्चाओं को और हवा दे दी है, कुछ लोग इसे खुले शब्दों में 'ऑनलाइन सिस्टम के पीछे ऑफलाइन सेटिंग' कहने लगे हैं।

डिजिटल इंडिया का सपना और जमीनी हकीकत

केंद्र और राज्य सरकारें लगातार डिजिटल इंडिया और ई-ऑफिस की बात करती हैं,सरकारी विज्ञापनों में यह दावा किया जाता है कि अब पारदर्शिता बढ़ रही है और भ्रष्टाचार कम हो रहा है,ऑनलाइन व्यवस्था के मुख्य उद्देश्य थे मानव हस्तक्षेप कम करना,रिश्वतखोरी रोकना,समय बचाना और पारदर्शिता बढ़ाना,लेकिन यदि आवेदकों को फिर भी राजधानी पहुंचकर अधिकारियों से मुलाकात करनी पड़ रही है,तो इसका सीधा मतलब है कि व्यवस्था कहीं न कहीं अपने उद्देश्य से भटक रही है, ऑनलाइन प्रक्रिया का असली मतलब यह नहीं कि सिर्फ आवेदन इंटरनेट पर भर दिया जाए, असल पारदर्शिता तब होगी जब आवेदन की स्थिति सार्वजनिक हो, हर चरण की समय सीमा तय हो, देरी का कारण पोर्टल पर दिखे, और बिना किसी व्यक्तिगत संपर्क के कार्य पूर्ण हो जाए।

'नगर नारायण' के बिना फाइल नहीं चलती?

विभागीय चर्चाओं में एक शब्द बार-बार सुनाई देता है नगर नारायण, आम बोलचाल में इसे सुविधा शुल्क या अनौपचारिक लेन-देन के संकेत के रूप में देखा जाता है, सूत्र दावा करते हैं कि कई मामलों में लाइसेंस संबंधी फाइलें लंबे समय तक लंबित रहती हैं, लेकिन 'व्यवस्था' होने के बाद अचानक तेजी से आगे बढ़ जाती हैं,यदि ऐसा हो रहा है,तो यह न सिर्फ भ्रष्टाचार का मामला है बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ा गंभीर मुद्दा भी है,क्योंकि ब्लड बैंक और दवा कंपनियां सीधे जनता के स्वास्थ्य से जुड़ी संस्थाएं हैं, ऐसे संस्थानों में यदि लाइसेंसिंग प्रक्रिया पारदर्शी नहीं होगी, तो उसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं।

सवाल सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं,सुरक्षा का भी है...

ब्लड बैंक और दवा निर्माण कंपनियां अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र हैं,यहां किसी भी प्रकार की लापरवाही सीधे मरीजों के जीवन को प्रभावित कर सकती है,यदि लाइसेंस 'योग्यता' की बजाय 'प्रभाव' या 'प्रबंधन' के आधार पर मिलने लगें, तो यह बेहद खतरनाक स्थिति होगी, विशेषज्ञ मानते हैं कि ब्लड स्टोरेज,संक्रमण जांच, दवाओं की गुणवत्ता, लैब मानक,और तकनीकी निरीक्षण जैसी प्रक्रियाओं में किसी भी प्रकार का समझौता जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है, इसलिए लाइसेंसिंग व्यवस्था पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी होना आवश्यक है।

मुख्यालय में बैठने वालों का डेटा सार्वजनिक होना चाहिए...

अब मांग उठने लगी है कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग इस पूरे मामले में पारदर्शिता लाए,विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि विभाग को सार्वजनिक रूप से यह जानकारी जारी करनी चाहिए कितने आवेदन लंबित हैं,कितने स्वीकृत हुए,कितने निरस्त हुए,प्रत्येक आवेदन में कितना समय लगा,और कितने आवेदकों ने व्यक्तिगत रूप से मुख्यालय का दौरा किया,यदि सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है,तो फिर व्यक्तिगत मुलाकातों का रिकॉर्ड भी सार्वजनिक होना चाहिए।

क्या सरकार करेगी निष्पक्ष जांच?

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राज्य सरकार इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराएगी? क्या यह पता लगाया जाएगा कि मुख्यालय में भीड़ क्यों लगती है? ऑनलाइन प्रक्रिया के बावजूद व्यक्तिगत संपर्क की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्या कहीं बिचौलिया तंत्र सक्रिय है? क्या लाइसेंस प्रक्रिया में अनियमितता या आर्थिक लेन-देन की शिकायतें सही हैं? यदि सरकार वास्तव में पारदर्शिता चाहती है, तो उसे इस पूरे सिस्टम का ऑडिट कराना चाहिए।

जनता पूछ रही—ऑनलाइन सुविधा या ऑफलाइन मजबूरी?

आज आम जनता भी यह सवाल पूछ रही है कि जब सरकार हर विभाग को ऑनलाइन करने का दावा करती है,तो फिर लोगों को राजधानी में जाकर 'दरबार' लगाने की जरूरत क्यों पड़ती है? यदि ऑनलाइन प्रक्रिया के बावजूद फाइलें व्यक्ति विशेष की कृपा पर निर्भर रहेंगी,तो डिजिटल व्यवस्था का पूरा उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा, ब्लड बैंक और दवा कंपनियां सिर्फ व्यवसाय नहीं, बल्कि जनस्वास्थ्य से जुड़ी जिम्मेदार संस्थाएं हैं,इसलिए इनकी लाइसेंस प्रक्रिया पर उठ रहे सवालों को हल्के में नहीं लिया जा सकता,अब देखना यह होगा कि सरकार इन सवालों का जवाब देती है या फिर 'ऑनलाइन सिस्टम' के पीछे चल रही 'ऑफलाइन व्यवस्था' यूं ही जारी रहती है।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी सुनवाई...फ्यूल बचाने बदलाव

समर वेकेशन में कोर्ट नहीं जाएंगे जज

बिलासपुर,20 मई 2026। सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी ईंधन और संसाधनों की बचत के लिए अपने कामकाज में बदलाव किए हैं। हाईकोर्ट में समर वेकेशन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के निर्देश पर सर्कुलर जारी किया गया है। इस आदेश के बाद भीषण गर्मी में वकीलों और पक्षकारों को कोर्ट आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि, जो वकील किसी कारणवश वर्चुअली नहीं जुड़ पाएंगे, उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने की अनुमति रहेगी। जरूरत पड़ने पर कोर्ट खुद भी फिजिकल सुनवाई के निर्देश दे सकेगा।

कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम

हाईकोर्ट और जिला अदालतों के कर्मचारियों को सप्ताह में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जा सकती है। हालांकि, रोटेशन व्यवस्था के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कम से कम 50 प्रतिशत कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित रहें।

फ्यूल बचाने के लिए जज-अधिकारी करेंगे कार पूलिंग

फ्यूल की बचत और सरकारी संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए हाईकोर्ट ने नई पहल की है। इसके तहत राज्य के न्यायिक अधिकारियों, रजिस्ट्री अफसरों और मंत्रालयीन कर्मचारियों के लिए व्हीकल पूलिंग यानी साझा वाहन व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट के जजों से भी आपस में कार-पूलिंग करने का आग्रह किया गया है।

रजिस्ट्री को तैयारियों के निर्देश

इन सभी व्यवस्थाओं को बिना किसी बाधा के लागू करने के लिए हाईकोर्ट रजिस्ट्री के अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सहित अन्य जरूरी तकनीकी इंतजाम दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। हाईकोर्ट प्रशासन का कहना है कि रमेश सिन्हा के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट तकनीक, आपसी समन्वय और संस्थागत जिम्मेदारी के जरिए आम जनता के लिए न्याय सुलभ बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

कोयला घोटाला...अवैध वसूली के पैसे रजनीकांत के पास जमा किए

सूर्यकांत के ड्राइवर के खिलाफ 5 वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश, 7.5 करोड़ अफसरों तक पहुंचाया

रायपुर,20 मई 2026। छत्तीसगढ़ कोयला लेवी घोटाला मामले में ACB-EOW ने कारोबारी सूर्यकांत तिवारी के ड्राइवर नारायण साहू के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की है। जांच एजेंसी के अनुसार, अब तक इस मामले में एक मूल और 5 पूरक चालान पेश किए जा चुके हैं। आरोपी नारायण साहू फिलहाल रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद है। ACB-EOW की जांच में सामने आया है कि, नारायण साहू अवैध कोल लेवी वसूली सिंडिकेट का एक्टिव सदस्य था। वह कथित तौर पर

मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी के कहने पर कोयला कारोबारियों और ट्रांसपोर्टरों से अवैध कैश वसूली करता था। EOW के मुताबिक, आरोपी नारायण साहू वसूली गई रकम को कलेक्ट कर सूर्यकांत के भाई रजनीकांत तिवारी के पास जमा करता था। जांच में यह भी सामने आया है कि अवैध वसूली की रकम से करीब 7.5 करोड़ रुपए कैश राज्य सेवा अधिकारी सौम्या चौरसिया और निलंबित IAS समीर विश्नोई समेत कई लोगों तक पहुंचाई गई।

कई आरोपियों की भूमिका की जांच जारी : एजेंसी ने बताया कि, मामले में पहले से पेश अभियोग पत्रों के साथ अतिरिक्त साक्ष्य भी अदालत में प्रस्तुत किए गए हैं। वहीं, इस मामले में अन्य संभावित आरोपियों की भूमिका की जांच अभी जारी है।

क्या है 570 करोड़ से ज्यादा का कोल स्कैम : ED का दावा है कि छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाला किया गया है। इस मामले में 36 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। ईडी का आरोप है कि कोयले के परिचालन, ऑनलाइन परमिट को ऑफलाइन करने समेत कई तरीकों से करीब 570 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध वसूली की गई थी।

2 पूर्व मंत्रियों,विधायकों समेत 36 पर FIR : छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाले मामले में ED की रिपोर्ट पर ACB /EOW ने दो पूर्व मंत्रियों, विधायकों सहित 36 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की है। जिस पर अब ACB-EOW की टीम जांच कर रही है। इस मामले में IAS रानू साहू के अलावा IAS समीर विश्नोई, सौम्या चौरसिया, जेडी माइनिंग एसएस नाग और कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को गिरफ्तार किया गया था।

छत्तीसगढ़ महिला-बाल विकास विभाग में तबादला...11 परियोजना अधिकारी और 30 पर्यवेक्षक बदले गए

रायपुर,20 मई 2026। महिला एवं बाल विकास विभाग में राज्य सरकार ने बड़े स्तर पर तबादला किया है। बड़ी संख्या में 11 परियोजना अधिकारियों और 30 पर्यवेक्षकों के प्रभार में बदलाव करते हुए नई पदस्थापना सूची जारी की है। इसमें सरगुजा, कोरिया, बलरामपुर, रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, कांकेर, कोण्डागांव, बीजापुर, बेमेतरा, बालोद, जशपुर समेत कई जिलों में परियोजना अधिकारियों के प्रभार बदले गए हैं।

छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर,100 एकड़ सरकारी जमीन मुक्त....

राजनांदगांव,20 मई 2026। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में प्रशासन ने भू-माफियाओं और अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक कार्रवाई को अंजाम दिया है। प्रशासनिक टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए करीब 100 एकड़ बेशकीमती सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से पूरी तरह मुक्त करा लिया है। इस व्यापक अभियान के दौरान नियमों को ताक पर रखकर विकसित की जा रही अवैध प्लाटिंग, अवैध रूप से निर्मित मैरिज पैलेस और अन्य कई पक्के निर्माणों को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया गया। शुरुआती जांच और सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक, इस पूरी अवैध गतिविधि के तार दुर्ग जिले के एक बेहद रसूखदार और बड़े व्यवसायी से जुड़े हुए हैं, जिसने लंबे समय से इस सरकारी भूभाग पर अपना शिकंजा कस रखा था। यह पूरी बड़ी कार्रवाई राजनांदगांव के कलेक्टर जितेंद्र यादव के कड़े और स्पष्ट निर्देशों के बाद अमल में लाई गई है। कलेक्टर के आदेश पर राजस्व और प्रशासनिक अधिकारियों की एक संयुक्त टीम का गठन किया गया, जिसने मौके पर पहुंचकर अवैध रूप से संचालित हो रहे एक आलीशान मैरिज पैलेस को मलबे में तब्दील कर दिया। इसके साथ ही, जमीन की खरीद-बिक्री के लिए की गई अवैध प्लाटिंग और बाउंड्रीवॉल को पूरी तरह से हटा दिया गया। कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े और किसी भी संभावित विरोध से निपटा जा सके, इसके लिए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीणों और राहगीरों की भीड़ भी इस बड़ी कार्रवाई को देखने के लिए एकत्रित हो गई थी। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक, इस सुनियोजित अवैध कब्जे और अवैध प्लाटिंग के खेल के कारण सरकारी खजाने और राजस्व को भारी चपत लग रही थी।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफसेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)